l।ln e। cgl

राष्ट्रपति अभिभाषण

- Jh ykyd".k vkMok.kh
- **Jherh l|"kek Lojkt**
- Jh v#.k tVyh
- Jh v#.k 'kkjh
- Jh dyjkt feJ

Hkkjrh; turk ikVh

प्रकाशकीय

पन्द्रहवीं लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संयुक्त सदन को सम्बोधित किया। सम्बोधन के पश्चात दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई। इस चर्चा में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी व उप नेता श्रीमती सुषमा स्वराज तथा राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली व श्री अरूण शौरी, कलराज मिश्र आदि कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया।

प्रमुख विपक्षी दल के नाते भाजपा ने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को सकारात्मक विपक्ष के रूप में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया वहीं यह भी कहा कि यदि जनहित और राष्ट्रहित के कार्यों में केन्द्र सरकार कोई कोताही बरतेगी तो हम सदैव एक सशक्त प्रहरी की भूमिका भी निभाएंगे।

हम यहां कुछ प्रमुख भाषणों का पूरा पाठ इस पुस्तिका में प्रकाशित कर रहे हैं।

i|dk'kd
Hkkjrh; turk ikVh

tu 2009

लोकसभा

सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी भाजपा

& ykyÑ".k vkMok.kh

माननीय अध्यक्ष महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अभी जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चाको जी ने अपनेअंतिम वाक्य में कहा कि मैं आशा करता हूं कि यह धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होगा। यह इस सदन की परम्परा है कि अभिभाषण पर अगर कुछ कहना भी है, तो भी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संशोधन दिया जाता है कि मुझे खेद है कि उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का पूरा सदन हमेशा समर्थन करता है और वह सर्वसम्मति से ही पारित होता है। अध्यक्ष महोदया, आज यह पहली बहस है, जिस पर आप अध्यक्षता कर रही हैं। एक प्रकार से संसदीय इतिहास में भी एक अनूठी घटना घटी कि पहली बार एक महिला यहां की अध्यक्षा बनीं और एक ही प्रकार से महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक सशक्तीकरण हुआ, दोनों एक साथ ही हो गये। मैंने जैसे परसों कहा था कि मैं भूल नहीं पाता हूं कि मुझे आपके स्वर्गीय पिताजी के साथ मंत्रिमंडल में भी काम करने का अवसर मिला और उनकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से हम सभी प्रभावित थे। वे निर्णय करने में देर नहीं लगाते थे। देश, समाज और राष्ट्र के हित में जो भी उचित लगता था, वे उस बारे में शीघ्र निर्णय करते थे।

पन्द्रहवीं लोक सभा का यह पहला अधिवेशन है। इस अवसर पर मैं अपना पहला भाषण करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि वे देश के प्रधान मंत्री एक चुनाव में से उभरकर बने हैं। सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी, यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी समेत सभी को मैं बहुत–बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें वर्ष 2009 के चुनाव में जनादेश मिला है और वर्ष 2004 से भी बड़ा जनादेश मिला है। भले ही वैसा न मिला हो, जिस कारण कई लोगों ने बड़ी आशाएं प्रकट कीं कि यह होगा, वह होगा। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि शायद सबसे बड़ा जनादेश किसी को मिला, तो वर्ष 1984 में श्री राजीव गांधी जी को मिला। उन्हें सबसे बड़ा जनादेश मिला।

मुझे स्मरण नहीं है कि कभी चार सौ से अधिक सांसद पंडित जी के साथ या इंदिरा जी के साथ भी रहे थे, जितने राजीव जी के साथ थे, लेकिन बावजूद इसके अगले ही चुनाव में परिणाम बिल्कुल दूसरे हो गए। वह चुनाव एक प्रकार से हर सरकार को चेतावनी देता है कि कि जनता पूरे समय आपके कार्यों का निरीक्षण करती रहती है और इतनी बड़ी संख्या में जीतने के बाद भी अगला परिणाम दूसरा भी हो सकता है। हिन्दुस्तान में ऐसा लगातार होता रहा है, मैं केवल वर्ष

1984 और वर्ष 1989 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह हमेशा मानता हूं कि हिंन्दुस्तान ने सारी दुनिया में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है संसदीय लोकतंत्र को सफल बनाने का। जब हमने वर्ष 1950 में इसे अपनाया था तो उन दिनों के जो विश्लेषणकर्ता थे, विद्वान थे, खासकर पश्चिम में, वे इस प्रकार से आशंका प्रकट करते थे कि इन्होंने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जो मूलभूत परिस्थितियां किसी देश में होनी चाहिए, वह तो यहां नहीं हैं। यहां पर लोग शिक्षित नहीं हैं, पढ़े–लिखे नहीं हैं। लोग मजाक करते थे कि यहां पर अंगूठा छाप लाखों लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है। लोग यह भी कहते थे कि प्रैक्टिकली पूरे हिंन्दुस्तान में, बाकी सब पार्टियां छोटी–छोटी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्षों तक यहां इस संसद में, लोक सभा में कोई रिकग्नाईज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं बन पाई क्योंकि रिकग्नाईज्ड अपोजिशन पार्टी के लिए 54 सदस्य होने चाहिए, कम से कम कोरम चाहिए जो नहीं बन पाया। यह सब कुछ होते हुए भी जिस प्रकार से 60 साल तक भारत ने संसदीय लोकतंत्र को संचालित किया है, उससे सारी दुनिया में हमारी साख बनी है और मैं मानता हूं कि वर्ष 2009 के चुनाव उस साख में और वृद्धि करते हैं।

हमारा लोकतंत्र केवल इसीलिए उल्लेखनीय नहीं है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स यहां पर हैं, लेकिन इसलिए भी उल्लेखनीय है कि हमारा लोकतंत्र न केवल सबसे बड़ा है, बल्कि एक सजीव लोकतंत्र भी है, जहां पर जनता सोच–विचार कर अपना निर्णय करती है। मैं इस अवसर का उपयोग इन चुनाव परिणामों के विश्लेषण के लिए नहीं करूंगा। यह इसका अवसर नहीं है। मैंने केवल एक वाक्य कहा था कि जनता का यह जो निर्णय है, यह जो जनादेश है, It is a mandate for stability and it is a mandate for bi-polarity मैंने यह वाक्य कहा था। मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं लेकिन मैं केवल स्टेबिलिटी की बात कहना चाहूंगा। जैसी स्टेबिलिटी राजीव जी की सरकार को मिली थी, यह वैसी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी मिली है। दिशा स्टेबिलिटी की है। यह दिशा आगे बढ़े, यह मैं चाहूंगा।

मैं मानता हूं कि हिंन्दुस्तान में जो गठबंधन बनते हैं, उनके प्रति लोगों के मन में आशंका होती है कि क्या यह गठबंधन स्थिर रहेगा, यह टिक पाएगा? इसीलिए जहां पर गठबंधन टिकाऊ दिखते हैं, वहां पर आम मतदाता वोट देता है और अगर टिकाऊ नहीं दिखते हैं तो फिर उसकी प्रवृत्ति होती है किसी एक मजबूत पार्टी को वोट देने की। मुझसे कभी–कभी लोग पूछते हैं कि आपकी पार्टी के पूरे इतिहास में आप अपनी पार्टी की कौन सी उपलब्धि को सबसे प्रमुख उपलब्धि मानेंगे, तो मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यह मानता हूं कि वर्ष 1950 में भारत का संविधान बना, वर्ष 1951 में मेरी पार्टी बनी, वर्ष 1952 में पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमारी पार्टी को केवल तीन सीटें मिलीं।

भारतीय जनसंघ को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में केवल तीन सीटें मिलीं। फिर भी उन्होंने कॉंश्यसली पहली–पहली लोक सभा में एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, जिसमें अनेक पार्टियां थीं। वह गठबंधन का पहला–पहला प्रयास। उसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया था– नेशनल डेमोक्रटिक फ्रंट। बाद में

जब वाजपेयी जी की सरकार बनी, कई दलों के सहयोग से कॉलीशन गवर्नमेंट बनी, तब हमने फ्रंट के बजाए एलायंस शब्द का प्रयोग किया और हमने कहा कि नेशनल डेमोक्रटिक एलायंस। आम जनता देखती है कि क्या ये टिके रहते हैं या नहीं, ये स्थिर रहते हैं या नहीं। मैं मार्क्सवादियों की चाहे जितनी आलोचना करता रहूं, लेकिन मैं कहता हूं कि उनका लेफ्ट फ्रंट एक पूरा टिकाऊ गठबंधन है। वह ठीक प्रकार से स्थिरता से चलता है, मैं इसे मानता हूं। लेकिन मैं उनसे शिकायत करता हूं कि उन्होंने जिस समय सन् 2004 में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, तब इस कारण नहीं किया कि वे कोई हमेशा उनसे टिके रहना चाहते थे। वे उनकी नीतियों को, उनके निर्णयों को प्रभावित करना चाहते थे और साथ–साथ उनका अगर कोई उद्देश्य था तो वह एक नकारात्मक उद्देश्य था कि आखिर इनकी प्रमुख विरोधी बीजेपी है और बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने पहले कभी ऐसे समर्थन नहीं दिया, सिर्फ 2004 में दिया। इसीलिए मैंने तब भी कहा था आपको और आपके मित्रों को कि एक बार आपकी सहयोगी पार्टी सीपीआई ने पहले यही प्रयोग किया था, उसका परिणाम उसे कितना भुगतना पड़ा, वह आपको यानी सीपीआई (एम) को अब भुगतना पड़ा है। लेकिन यह तो एक नकारात्मक कारण था, अन्यथा आप उसी समय कह देते कि आपने अगर अमेरिका से मित्रता की, तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ होंगे। आप डॉ. मनमोहन सिंह जी को उसी समय यह कह देते।

आपने जो कुछ कहा, वह सबको पता है। देश ने उसके आधार पर निर्णय किया है। लेकिन हां, स्थिरता का महत्व है। इसीलिए मैं ट्रेज़री बैंचेज़ पर बैठे हुए मंत्रियों को कहूंगा, stability is not for is self. Stability is for good performance; stability is for good governance, stability is for development, and stability is also for security. मैंने तीन शब्द वही प्रयोग किए हैं, जो हम अपने पूरे अभियान में करते रहे थे। It is good governance, development and security. These are the three things. इसमें हमारी कोई मोनोपली नहीं है, हमारा कोई यह कॉपीराइट नहीं है। But these are touchestones which make the voters judge whether we have made this Government a stable Government. Are they discharging their duty accordingly? So, they will be watching it closely.

मैं आज के अवसर पर शुरू में इतना ही कहूंगा कि हम विपक्ष में हैं। हमारी संख्या में पहले से कमी हुई है। पिछली बार हमारी स्ट्रैंथ 138 थी, इस बार 116 है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 116 भी कोई कम स्ट्रैंथ नहीं है, अच्छी–खासी है। यह ठीक है कि आप 200 के ऊपर हो गए, लेकिन क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। पहले की कांग्रेस की सरकारों को कितनी क्लियर मेजोरिटी मिलती थी, राजीव जी को कितनी मिली थी, वह स्थिति नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, सरकार और विपक्ष के बीच सम्बन्धों की एक नई शुरूआत हो, वह नई शुरूआत होगी तो उसका परिणाम संसद की कार्यवाही पर भी निश्चित रूप से होगा। जितने संकेत मुझे अभी मिले हैं, मैं मानता हूं कि शायद नई शुरूआत होगी, जरूर होगी।

मैं एक सदस्य हूं जिसने 1952 के चुनाव में एक कैम्पेनर के नाते भाग लिया। सन् 1952 से लेकर सन् 2009 तक के चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसलिए जो हमारे लोकतंत्र का इवोल्यूशन हुआ है, इस सिस्टम का, उसे प्रत्यक्ष

रूप से देखा है।

इसलिए जैसा मैने कहा कि डा. मुखर्जी ने जब नेशनल डैमोक्रटिक फ्रंट बनाया, तो पहले हमें समझ में नहीं आया कि तीन लोगों की पार्टी हमारी तो फ्रंट काहे के लिए बनाते हैं, जिसमें गणतंत्र फ्रंट उड़ीसा को जोड़ा, जिसमें अकाली दल पंजाब को जोड़ा और आगे बढक़र अकाली दल के साथ सबसे पहले समझौता करके एक कॉलिशन गवर्नमेंट जस्टिस गुरनाम सिंह की बनाई थी।

डा. लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डा. मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब के सब उन महापुरुषों में जिन्होंने इस बात को नोट किया कि दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि इस देश में एक ही पार्टी छाई रही तो फिर लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। इसीलिए सिस्टमैटिकली हमने अप्रोच अपनाई कि किस प्रकार से यह जो कांग्रेस पार्टी की हैजीमनी है, मौनोपली ऑफ रूल है, उसे कैसे तोड़ा जाए। उसे तोड़ने में सफल हुए, इसीलिए बाईपोलर पॉलिटी बनी। सन् 1984 वाला समय आया, जब हम केवल दो सीटें ही पूरे हिंदुस्तान में प्राप्त कर सके। लेकिन सन् 1998 आते–आते हम सदन की सबसे बड़ी पार्टी बन गये और अपनी सरकार बनाकर हमने 6 साल तक देश पर राज किया – यह भी सच्ची बात है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी एम्बीशन्स हैं, आपकी हमारी और देश की जनता की भी हैं कि यह शताब्दी जो अभी बहुत लम्बी है, अभी तो वर्ष 2009 ही है, अभी–अभी एक घटना घटी, जिस घटना के बारे में हमारी प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली माननीया गिरिजा व्यास जी ने कहा कि मैंने आडवाणी जी का भाषण पढ़ा और जिस भाषण से मैं सहमत हूं। मुझे लगा कि मुम्बई कि 26–11–2008 की घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, कोई साधारण आतंकवादी हमला नहीं था।

महोदया, पिछले कई सालों से आतंकवादी हमले लगातार होते रहे हैं। मुम्बई की घटना 26/11 के हमले को तीन दिन तक लगातार देश की जनता ने टीवी पर देखा, तो एक धारणा बनी कि यह कोई घटना नहीं है। यह कोई अकेला हमला नहीं है। कम से कम टेलीविजन से यह आभास मिला। हम लगातार यह कहते हैं कि तीन–तीन युद्धों में पराजित होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल कर इस प्रोक्सी वार की रणनीति अपनाई। इसके बाद जनरल जिया ने तय किया कि अब इसके बाद सीधा युद्ध नहीं करना है, बल्कि अप्रत्यक्ष युद्ध आतंकवाद के माध्यम से करना है, मैं मानता हूं कि 26/11 की घटना ने यह अहसास पूरी दुनिया को दिया और एक प्रकार से सारी दुनिया को भी दिया। हमें इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि 26/11 की घटना का मास्टर माइंड हाफिज़ था। जिस मास्टर माइंड को हमारे प्रयत्न से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपने रेज्युलूशन 1267 में कहा कि हाफिज़ का अलकायदा से संबंध है, तालिबान से संबंध है। हाफिज़ सईद को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ कर गिरफ्तार भी किया, लेकिन अचानक कोर्ट ने उसे छोड़ दिया और कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर, जो गवाही दी गई है, एविडेंस किया गया है, वह एडिक्वेट नहीं है। पाकिस्तान सरकार कहेगी कि यह कोर्ट का फैसला है। पाकिस्तान सरकार यह कह कर बचने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान की कोर्ट्स का क्या हाल है, वहां क्या–क्या होता है, उस बारे में मैं यहां टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान को इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारे पास जितना एविडेंस था, वह हमने प्रस्तुत किया है। पाकिस्तान सरकार के पास तो किसी

प्रकार का एविडेंस नहीं था। हमारे एविडेंस के आधार पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हाफिज़ के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपना केस कोर्ट में प्रस्तुत किया, उसके कारण हाफिज़ रिहा हो गया। लश्करे तोयबा का रिलिजस पालिटिकल फ्रंट जमात उद दावा है। गृह मंत्री चिदम्बरम जी सदन में उपस्थित हैं, मैं मांग करता हूं कि हाफिज़ के संदर्भ में, 26/11 की घटना के संदर्भ में, हमने जो एविडेंस पाकिस्तान सरकार को दिए हैं, उन एविडेंस को सदन के साथ शेयर करें। देश को भी पता लगे कि हमने पाकिस्तान को क्या–क्या एविडेंस दिए हैं, जिसके आधार पर वह कोर्ट में गए। मुझे विश्वास है कि देश को संतोष होगा। हम उनके ऊपर दबाव बढ़ाते रहें, अंतर्राष्ट्रीय विश्व के लोग भी उन पर दबाव डालते रहें कि उस पर कार्यवाही हो, तभी इस बारे में हमें सफलता मिलेगी।

महोदया, मैं जानना चाहूंगा कि जिस 26/11 की घटना के दौरान जिंदा पकड़े गए एकमात्र व्यक्ति कसाब को, जिसे पुलिस कांस्टेबल के साहस तथा उसके बलिदान के कारण पकड़ सके, उस कसाब के केस में क्या प्रगति हुई है? मैं चाहूंगा कि इस केस में विलम्ब नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैंने जो बात पहले कही, उसके लिए मैं एक पाकिस्तानी पत्रकार याहिद हुसैन की बात को कोट करना चाहूंगा, जो लेखक भी हैं। उन्होंने फ्रंट लाइन पाकिस्तान पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लश्कर–ए–तोयबा और आईएसआई के संबंध बिल्कुल अटूट हैं।

प्रणव जी ने कहा कि हमने यह सफलता पायी है कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना पडा कि जो लोग आए थे वे पाकिस्तानी थे लेकिन उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। वह कहते थे कि स्टेट का कोई संबंध नहीं है, लश्कर–ए–तोएबा के होंगे, जो टैरारिस्ट ऑर्गेनाइजेशन्स हैं. वे उनके साथ जुड़े होंगे लेकिन राज्य का कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा कांड हो, इतना भयंकर कांड हो, इतना नियोजित कांड हो और उसमें वे समुद्र के रास्ते से आएं, इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार में किसी को पता न हो, आईएसआई ने ही प्लान किया होगा, ऐसी हमें आशंका है और खास तौर पर पाकिस्तान के याहिद हुसैन की पुस्तक पढने़ के बाद लगा कि निश्चित रूप से उन्होंने किया होगा लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री जी इसका जवाब दे सकेंगे क्योंकि इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने जांच करने के लिए एक टू मैम्बर कमेटी आर.डी. प्रधान की बनायी। आर.डी. प्रधान कमेटी ने जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार को कहा कि उनका कोई दोष नहीं है। उन्हें बरी कर दिया। अगर किसी का दोष है तो सैंट्रल गवर्नमेंट का है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई कमेटी इतने बड़े कांड के लिए राज्य सरकार की बने और वह यह कहे कि हमारा कोई दोष नहीं है। इसमें अगर कोई विफलता हुई है तो केन्द्र सरकार की हुई है।

इतना ही नहीं, अभी तक हमने नहीं किया होगा। आज यह अवसर है जब पहली–पहली हमारी सभा हो रही है और चिदम्बरम जी स्वयं कहें कि मैं इस बात से सहमत हूं और प्रधान मंत्री जी को रिकमेंड करें कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाइए जो इस बात की पूरी जांच करे और उठाकर उसको भी देखे कि जो आर.डी. प्रधान कमेटी की रिपोर्ट है, पैनल की रिपोर्ट है, वह कैसे हुई है? आखिर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया,

वहां के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दिया, वहां के सहयोगी ने इस्तीफा दिया। मेरी एक चौथी डिमांड है कि यह होना चाहिए।

मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं जरूर इस बात का उल्लेख करूंगा और मुझे इस बात की खुशी है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत दिनों से सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों की जो इच्छा रही है, उनकी वन रैंक वन पेंशन की जो बहुत आकांक्षा रही है, उसका उल्लेख इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में है तथा मैं उम्मीद करता हूं कि जून के महीने तक यह रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें उनकी इस मांग को स्वीकर किया जाएगा क्योंकि इसमें इस मांग को स्वीकार करने की बात नहीं है। शायद आपके इस बार के घोषणा–पत्र में भी नहीं थी लेकिन अच्छा होगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए।

अब मैं विकास के मुद्दों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जिनका इसमें उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत अच्छी बात कही गई है:

"While male literacy went up to over 75 percent is the last census and is expected to be higher now, female literacy was only 54 percent in 2001."

फिर उन्होंने कहा है कि–

"My Government will recast the National Literacy Mission as a National Mission for Female Literacy to make every woman literate in the next five years."

मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। बहुत उचित है क्योंकि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि एक लड़के को शिक्षित करने का मतलब होगा कि देश में शिक्षितों की संख्या में एक बढ़ाना है लेकिन एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब है कि देश में शिक्षितों का एक परिवार बढ़ाना है। इसीलिए मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। इस मामले में कई प्रदेशों में भी अपने–अपने ढंग से कार्रवाई हो रही है। मैं उन प्रदेशों को भी जानता हूं कि जहां मेरे सहयोगी वहां कार्य कर रहे हैं। यह काम ऐसा है कि जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर काम आगे बढ़ाएं। विकास के कार्यों में क्रडिट किसको मिलता है, इस चक्कर में ज्यादा न पड़ें। अच्छी बात है कि अगर हमारी सरकार कोई काम करती है या केन्द्र की सरकार करती है– यदि केन्द्र की सरकार करती है तो केन्द्र को क्रेडिट मिलेगा। प्रदेश की सरकार करती है तो प्रदेश को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन क्रेडिट किसको मिलेगा, इसके आधार पर कोई फैसला नहीं होना चाहए। मेरा अनुरोध है कि अच्छे काम होने चाहिए।

मैंने जब मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना देखी तो मुझे लगा कि लिटरेसी ही नहीं, लड़की को स्कूल भेजने के बाद, वह स्कूल में भर्ती तो हो जाती है, लेकिन इतने ड्रॉप आउट्स होते हैं, लगातार उसके बाद ड्रॉप आउट होते जाते हैं। उस ड्रॉप आउट के दोष को रोकने के लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, जिसका उद्देश्य था कि जिस–जिस घर में लड़की का जन्म हुआ, उसे जन्म से लेकर जब तक वह बारहवीं पास नहीं करती, आगे नहीं पढती, तब तक उन्हें पीरियोडकली सहायता मिलती रहे। लेकिन जब वह बारहवीं पास कर लेती है तो उन्हें एक लाख बीस हजार रुपये मिलते हैं। इस योजना का वहां बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। मैं चाहूंगा कि सारे देश में सरकार इसे लागू

करे। यह बहुत अच्छा होगा। कुछ और प्रदेशों ने भी इस दिशा में काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे भी बहुत खुशी हुई, स्वाभाविक रूप से जब से अध्यक्ष महोदया आप आई हैं सब महिलाएं तब से बहुत प्रसन्न हैं। जब हम अध्यक्ष महोदया से उनके कक्ष में जाकर मिले थे, तभी यही बात सबसे आगे आई थी कि अब देखिये वूमैन्स रिजर्वेशन बिल पास हो जायेगा। मुझे कभी–कभी लगता है कि इतने साल लग गये, यह बिल बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इतने साल इसलिए लग गये कि शायद राष्ट्रपति भी महिला हो जाएं और स्पीकर भी महिला हो जाएं, तब इसे पास करेंगे। इसलिए इतनी प्रतीक्षा की। मैं फिर से अपनी पार्टी का स्टैंड दोहराना चाहूंगा कि आप जब भी इस बिल को लायेंगे, हमारी ओर से बिल पर पूरा समर्थन होगा। मुझे खुशी होती है कि मेरी अपनी पार्टी में यह लागू है, सरकार कब करती है, क्या करती है, हमने अपनी पार्टी में इसे अपने ढंग से जहां तक ऑफिस बियरर्स हैं, पार्टी की हमारी यूनिट्स हैं, कमेटियां आदि हैं, उनमें सबमें लागू कर दिया है।

यहां शिक्षा की बात हो रही थी। मैं शिक्षा संदर्भ में इस बात को दोहराना चाहूंगा कि एक समय था कि लिटरेसी का अर्थ था – क ख ग घ और ड. का ज्ञान देना, ए, बी, सी, डी, से लड़के, लड़कियों को परिचित कराना। आज शिक्षित करने का लिटरेट करने का अर्थ समझना चाहिए।

कंप्यूटर से भी एक–एक बालक और बालिका को स्कूल के समय परिचित कराना। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे अपने परिवारों में बच्चे जानते हैं, हम बहुत बार नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन वे समझते हैं। यह होता है, यह अच्छी बात है, क्योंकि लिटरेसी का अर्थ वही हो गया और फोर्मली सर्व शिक्षा अभियान में उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हम गांवों में उसे जितनी अधिक मात्रा में पहुंचा सकें, उतना हमें लाभ होगा। वैसे तो सर्व शिक्षा अभियान का भी इसमें उल्लेख है। इसमें इस बात का संकोच नहीं हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान हमारे डा.जोशी ने शुरू किया था, एन.डी.ए. की सरकार ने शुरू किया था। लेकिन उसका इसमें उल्लेख है और मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं यह सुझाव देता हूं कि इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी का कितना उपयोग कहां–कहां हो सकता है, न केवल ई.गवर्नेन्स के लिए, न केवल हैल्थ स्केयर के लिए, न केवल सुरक्षा के लिए, जहां–जहां भी आई.टी. का उपयोग हो सकता है, उसे करने की योजनाएं बननी चाहिए। हमने अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आई.टी,.विजन का एक डाकूमैन्ट जरूर बनाया है, उसका जितना उपयोग होगा, वह होगा। हां उसमें खास तौर पर बहुत समय से जो मेरे मन में बात थी, उसे आपने इस अभिभाषण में कहा है कि एक यूनीक आइडेंटिटी कार्ड देंगे, लेकिन उसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई है, यूनीक क्या होगा। मैं चाहूंगा कि भले ही वह यूनीक हो, अच्छा है, लेकिन यह मल्टीपरपज जरूर होना चाहिए।

हर चीज के लिए अलग कार्ड, राशन के लिए अलग कार्ड, वोटिंग के लिए अलग कार्ड और पैन कार्ड आदि नहीं होने चाहिए। एक ही कार्ड होना चाहिए, जो यूनीक हो और मल्टीपरपज हो, यह मेरा आग्रह रहेगा।

खासकर सुरक्षा की दृष्टि से यह आइडैंटिटी कार्ड बहुत लाभकारी है। दुनिया के अधिकांश बड़े बड़े देशों में है। पहले–पहले कभी कभी बाकी देशों को देखकर मेरे मन में चिन्ता आती थी कि जिस देश में 100 करोड़ से अधिक लोग रहते हों, वहां हर आदमी के लिये आइडैंटिटी कार्ड कम्पलसरी करना कितना कठिन

है और उसे बनाने में कितनी कठिनाई होगी? लोगों को भी कठिनाई होगी। इसलिये, तब से लेकर जब अभी इनफॉरमेशन टैक्नालाजी का आविष्कार हुआ है, कम्प्यूटर का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक यह चिन्ता मिट गई है। लोग कहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में सब से पहले दो इनवैन्शन हुये – पहला व्हील का और दूसरा इलैक्ट्रिसिटी का लेकिन मैं मानता हूं कि तीसरा हिस्ट्री का सब से बड़ा इनवैन्शन इंटरनैट का है। इसलिये देश को प्रगति की ओर बढ़ाने में उसका पूरा उपयोग होना चाहिये। केवलमात्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में इसका विकास होना चाहिये।

डा. गिरिजा व्यास ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि कांग्रेस सरकार कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई व्यक्ति रात में भूखा सोये? यह बहुत अच्छी बात है, भाव बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यूनिसैफ की एक रिपोर्ट पढक़र चिन्तित हुआ जिसमें कहा गया कि The number of hungry in India increased from 209.5 million in 2005&06 to 230 million by the end of 2007-08. उसके लिये मैं किसी को दोष नहीं देता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह चिन्ता का विषय है। इस चिन्ता के विषय को सारे हिन्दुस्तान को, केन्द्र सरकार को और सारी प्रदेश सरकारों को ग्रहण करना चाहिये। सब को मिलकर इस बात का जल्द से जल्द निश्चित रूप से प्रबंध करना चाहिये कि हिन्दुस्तान में एक भी बच्चा रात में भूखा न सोये।

अध्यक्ष महोदया, मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने चुनाव के दौरान स्विस बैंकों में पड़ी हुयी भारत की पूंजी की बात की थी तो मेरी कैसी आलोचना हुई थी। एक सज्जन, जो यहां नहीं हैं, ने मुझे पत्र लिखा जिसमें मुझे कहा गया कि झूठे हो, असत्य कह रहे हो। मैंने वह सहन कर लिया लेकिन ग्रहण भी कर लिया। फिर मैंने कहा कि It is not a question of dimension of the loot लेकिन यहां की सम्पत्ति ले जाकर विदेशों में जमा करा दी गई है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं देना चाहता था, टैक्स इवेजन के कारण वह पैसा वहां ले गया । वह चोरी का पैसा था, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा था, अब लूट कितनी है,यह डाइमैंशन का इश्यू है लेकिन फैक्ट यह है कि यह निर्विवाद है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने इस निर्विवाद सत्य को स्वीकार किया है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है और 'हां ' कहा है कि सरकार वह पैसा वापस लाने के लिये कदम उठा रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिये एफिडेविट में इस बात को स्वीकार किया है। एक सज्जन जो पुणे में हवाला का काम करता है, उसपर आई टी डिपार्टमेंट द्वारा 78 हजार करोड़ रुपया लेना बाकी है।

मुझे खुशी हुई कि इस इश्यू को कई पार्टियों ने समर्थन दिया। सीपीएम ने भी समर्थन दिया और जेडीयू ने भी समर्थन दिया। इतना ही नहीं, पोलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं बल्कि कई सारे धार्मिक नेता जिनकी बहुत फॉलोइंग है – सब लोग जानते हैं कि स्वामी रामदेव जी जब आसन करवाते हैं तो स्वामी रामदेव जी के कार्यक्रम में कितने हज़ारों लोग आते हैं और वे जब भी प्रवचन करते थे, इस स्विस बैंक में जमा भारतीय पूँजी का उल्लेख करना नहीं चूकते थे, हमेशा उल्लेख करते थे। मुझे अगर इस सरकार से थोड़ी शिकायत है तो इतनी है कि इसमें उल्लेख तो है कि हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया के 25 अप्रैल के इश्यू में मैंने पढ़ा कि 100

दिन की जो उनकी कार्य योजना है, उसमें इस विषय को जोड़ेंगे और सौ दिनों की जो योजना इसमें पढ़ी, मैं कल सुनता रहा, तो उसमें जब मैंने नहीं देखा तो मैं थोड़ा चकित हुआ। मैंने कहा प्रधान मंत्री ने स्वयं ने कहा लेकिन सौ दिन वाली इस योजना में उल्लेख नहीं हुआ। हो सकता है कि इनको कुछ कठिनाइयाँ लगती हों, मैं नहीं जानता सरकार में रहती हैं, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कि इसी संदर्भ में मैं इसका उल्लेख करूँगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भ्रष्टाचार शब्द का कोई उल्लेख नहीं है करप्शन के खिलाफ। टैरेरिज्म है, टैरेरिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरैन्स की बात भी चाको जी ने कही। बहुत अच्छी कही। वह जो गवर्नैन्स के संबंध में आपने बातें कही हैं सुधार की, उसमें करप्शन का ज़रूर उल्लेख होता और उस संदर्भ में भी जो रिकार्ड मेजॉरिटी मिली कांग्रेस गवर्नमैंट को राजीव जी के नेतृत्व में, वह रिकार्ड मेजारिटी क्यों चली गई उसका कारण भी एक करप्शन का ही इश्यू था जो बोफोर्स का कांड था, जिसके कारण वह सरकार चली गई और आपके तब के मंत्रिमंडल के एक सहयोगी भी आपसे अलग होकर आपके विरोधी हो गए। कुछ बातें मैं ज़िक्र करूँगा फॉरैन पॉलिसी की। वह यह है कि आस्ट्रेलिया के संबंध में सारा देश चिन्तित है। बहुत चिन्तित है कि आस्ट्रेलिया में इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि भारतीयों के प्रति इस प्रकार के अत्याचार और आक्रमण लगातार होते रहे और उस दिन टेलीविज़न पर मैं देख रहा था एक प्रदर्शन हो रहा था जिसमें पुलिस उनके साथ किस प्रकार व्यवहार कर रही थी, लड़कियाँ थीं, महिलाएँ थीं जो वहां पढती थीं, उनको किस प्रकार से उठा उठाकर उनके साथ व्यवहार हो रहा था, वह बहुत चिन्ताजनक था। इसीलिए देश में इसके बारे में बहुत चिन्ता है। आपने अपनी चिन्ता जताई है उनको।

उन्होंने भी जवाब दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी को वहां जाना चाहिए। आप एक डैलिगेशन यहां से भेज दें, पार्लियामैंट का एक डैलिगेशन चला जाए और वहां जाकर वहाँ पर बात करके आए तो अच्छा होगा। वे वहाँ की स्थिति भी समझकर आएंगे। उससे देश की चिन्ता निश्चित रूप से प्रकट होगी।

नेबरहुड का ज़िक्र किया गया है। नेबरहुड में पिछले दिनों में स्थिति खराब ही होती गई है। ठीक है कि नई सरकार आई है नेपाल में।

माधव जी, नेपाल के जो नये प्रधान मंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनको बधाई दी है। मैं आशा करता हूं कि एक नया अध्याय शुरु होगा, जिस अध्याय में भारत और नेपाल के जो परम्परागत संबंध रहे हैं, उनके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। विगत दिनों में ऐसा सोचा गया था कि जैसे मानो चीन का प्रभाव बढ रहा है, वह स्थिति चिन्ताजनक थी। मैं आशा करता हूं कि अब जो नयी सरकार आएगी, उसमें यह स्थिति बदलेगी। मुझे शिकायत है कि बंगलादेश के बारे में और वहां से लगातार हो रहे इल्लिगल इमीग्रेशन के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। वर्षों से हम इसके प्रति आंखें मूंद करके बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार की भर्त्सना की है, आईएमडीटी एक्ट के विषय को लेकर, उन्होंने यहां तक कह दिया– You are in a way collaborating with foreign aggression. उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गए। वैसे तो नयी सरकार आई है और इस सरकार की हमारे साथ अधिक मित्रता है। चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए,

लेकिन इस प्रक्रिया को चलाते हुए ऐसा एहसास कभी नहीं देना चाहिए कि We are bending backwards to satisfy them. पिछले दिनों जब यह खबर आई कि चीन पाकिस्तान के न्युक्लियर प्रोग्राम को और असीस्टेंस दे रहा है। यह एक ऐसा अवसर था कि जब भारत में चिन्ता पैदा होती थी। जिस प्रकार से लगातार चीन के लोग अरुणाचल के बारे में बोलते रहे हैं, वे सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें सही प्रतिक्रिया हर मामले में देनी चाहिए और मजबूती दिखानी चाहिए। विदेश के मामले में मुझे इतना ही कहना है। मैं एक बार फिर से डॉ. मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देकर यही कहूंगा कि देश देखता रहेगा, आपकी सरकार ने जो विश्वास लोगों को दिया है, उस विश्वास के अनरूप आप कैसे कार्य करते हैं। देश और संसद भी इन सारे कामों को मोनिटर करती रहेगी। मैं एक बार पुनः इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Synopsis

Madam Speaker,

I rise in support of the motion to give thanks to Respected Rashtrapatiji on her address to Parliament on the occasion of the beginning of the 15th Lok Sabha.

At the outset, it gives me immense pleasure to join the entire House in congratulating you warmly on your unanimous election as the Speaker of the 15th Lok Sabha. Your election has marked a proud milestone in the history of Indian Parliament. To see you in this august office is to see, simultaneously, an important triumph of both Social Justice and Gender Justice — both Social Empowerment and Women's Empowerment.

Madame Speaker, I had the honour of working with your illustrious father, as a fellow parliamentarian in the Sixth Lok Sabha (I was a member of the Rajya Sabha then) and also as a fellow minister in the Janata Party government. Babu Jagjivan Ram had built a great reputation for himself as one of the ablest administrators. He was a minister in every single government at the Centre, beginning with the Interim Government that Pandit Nehru headed soon after Independence. A learned man, he endeared himself to one and all in the House, cutting across party lines.

Madame Speaker, what is proved by you or your father or Dr. Ambedkar, who was the chief architect of the Indian Constitution, is that a PERSON BECOMES GREAT BY HIS OR HER KARMA, AND NOT BY JANMA.

THAT ALL HUMAN BEINGS ARE EQUAL AND THAT ALL HAVE THE DIVINE POTENTIAL IN THEM TO RISE TO THEIR FULL POTENTIAL.

I am sure that you too will raise the reputation of your high office with your erudition, impartiality, and long parliamentary and governmental

experience. I wish to solemnly pledge on this occasion that, in conducting the House, you can count on the fullest support from the Opposition benches — from my party as well as all other parties in the opposition.

This being the first session of the 15th Lok Sabha, I take this occasion to warmly congratulate Prime Minister Dr. Manmohan Singh, Leader of the House Shri Pranab Mukherjee, and Congress President and UPA chairperson Smt. Sonia Gandhi. The people have given a renewed mandate to the Congress party and the UPA government. It is indeed a bigger mandate than in 2004.

I take this opportunity to also congratulate both the old and new faces in the council of ministers.

No doubt, my party and the NDA are disappointed by the outcome of Elections 2009. But we have accepted the people's verdict with humility. Victory and defeat are a part of the electoral process. And this is not the occasion or the platform for an analysis of why the people preferred one party and one alliance over the other. Each of the parties in the opposition is engaged in its own analysis of the election results. Nevertheless, two broad comments are in order.

Firstly, irrespective of who won and who lost, the irrefutable fact is that the greatest victor is India's Democracy. Our country has shown once again to the world that ours is not only the largest democracy in the world because of numbers, but also the most vibrant. I remember that on many occasions in the past, especially after Independence, foreigners used to wonder if democracy can survive in this country of such immense diversity and so many illiterate people. They also used to be skeptical about the future of India as a united nation.

India has disproved all of them. Thus, the victory of India's democracy is our collective victory – the victory of the party and alliance that won, as well as the parties and alliances that lost.

Secondly, in my comments after the election results were known, I commented that the people have given their verdict in favour of stability and bipolarity. In recent days I have reflected upon the direction in which Indian politics is headed in the coming years. I will not say that regional parties and smaller parties have no place in national politics. Nor will I say, as Dr. Manmohan Singh did during the election campaign, that regional parties are an obstacle to growth. However, I do believe that the people want more cohesive alliances, in the absence of which they want to see national parties become stronger.

All of us, especially those in the treasury benches, should reflect on why the people have shown such strong preference for stability. Stability cannot be an end in itself. It is not a mandate for the government to

function any which way it wants for five years. Rather, the people want the government to be stable so that it can perform better. So that it can give a better account of itself on GOOD GOVERNANCE, DEVELOPMENT and SECURITY.

GOOD GOVERNANCE, DEVELOPMENT and SECURITY was the election plank of my party. However, there cannot be any monopoly or copyright on the three principles of GOOD GOVERNANCE, DEVELOPMENT and SECURITY. People expect every party or alliance that is elected to form the government to adhere to these principles.

Hence, I wish to assure the Prime Minister and the Leader of the House that my party and the NDA will extend full and constructive support to the government whenever we find that you are protecting the interests of the nation and advancing the interests of the people by adhering to GOOD GOVERNANCE, DEVELOPMENT and SECURITY. But when we find that you are doing otherwise, we shall certainly oppose the government both inside Parliament and outside.

Let the government do its duty. And we shall do our duty. By performing our respective duties, let us pledge today to jointly strengthen India's democracy and enhance the power and prestige of India's Parliament.

The din and drama of elections is over. Let us put behind us the acrimony of the election campaign. The new Lok Sabha has been constituted. The ministers have taken charge in their respective ministries. Let us begin a new chapter in government-opposition relations in the 15th Lok Sabha.

Madame Speaker, I now come to some of the substantive aspects of the President's Address to Parliament. Since the President's Address to Parliament is prepared and approved by the Cabinet as an account of what the new government intends to do and how it plans to address the many challenges before the nation, it is the duty of the opposition to look at it meticulously.

Release of Hafeez Saeed

I must express my deep disappointment over the rather cavalier and non-specific manner in which the government has mentioned the problem of terrorism in paras 9 and 42. The entire nation – indeed, the entire world – was horrified and outraged by the Pakistan-sponsored terrorist attack on Mumbai on 26 November 2008. The carnage is still fresh in the minds of the people. But there is another thing that has horrified, outraged and alarmed the people of India and the international community.

And that is the news a few days ago that the government of Pakistan,

by presenting a weak case before the Lahore high court, has allowed Hafeez Saeed, leader of the Jamaat-ud-Dawa, the hardline politico-religious front of the Lashkar-e-Taiba, and a mastermind of 26/11, to walk out of jail.

Saeed is accused of aiding and abetting the Mumbai attacks in the chargesheet filed by Mumbai Police. He is the head of the Jamaat-ud-Dawa and Lashkar-e-Taiba, which were listed by the United Nations under UNSC Resolution 1267, as being affiliates of al-Qaida and Taliban. Saeed was specifically listed as linked to these terrorist groups last year after India provided evidence about his involvement in terrorist strikes.

Pakistan government cannot hide behind the pretext that it is a court decision and hence cannot be interfered with. The entire world knows how independent the judiciary is in Pakistan. The media have reported that the court released Saeed on "technical" grounds — namely, lack of evidence. The evidence was lacking since the government of Pakistan simply did not furnish it before the court.

Pakistan cannot fool the world opinion with this kind skullduggery.

I know that the government has conveyed its displeasure to Pakistan. But, frankly, the government's response has been weak. It does not reflect the sense of outrage that the people of India have felt at the game of deception being played by Pakistan.

During the election campaign, Congress leaders claimed that the UPA government's "strong" approach to tackling terrorism was evident in the manner in which it had dealt with Pakistan after 26/11. The claim was: "Look, we got them to admit that Pakistani nationals were involved." It was as if Congress leaders were giving a certificate of sincerity and earnestness to the government of Pakistan. But look what has happened now.

26/11 : My four demands

Today, through the medium of this debate, I want to place four demands before the government. Firstly, it should place before this House the full evidence that the government of India has shared with the government of Pakistan on the involvement of Saeed and his accomplices in 26/11 and also in previous terrorist attacks in India. The people of India have a right to know all the facts and all the evidence that have so far come to light. Besides, by bringing this evidence into the public domain, India and the international community can put further pressure on Pakistan not to derail the trial of the leaders of the anti-India terrorist organizations operating from Pakistan.

But there is another reason why this evidence must be made public. Ever since 26/11, people in India and elsewhere in the world have been

asking one question: Was it only the handiwork of some Pak-based terrorist organizations or was there also some involvement of the ISI and other official agencies? This truth must also come out. For far too long, the rulers in Pakistan have been trying to fool the global community by pretending that terrorists belonging to organizations like the Lashkar-e-Toiba are independent actors. This falsehood must be nailed.

Renowned Pakistani journalist and author Zahid Husain, in his book FRONTLINE PAKISTAN, has written with a lot of well-researched information that Lashkar-e-Toiba's links with the ISI are unbreakable.

My second demand is that the government should place before the House evidence about Kasab, the only terrorist linked to 26/11 who was caught alive, and what has come out of his statements during the investigation.

My third demand is that the judicial trial of Kasab, which is now underway, should be completed as early as possible. People want to see that justice is delivered and done in this case without the kind of delay that unfortunately has been witnessed in many terrorist cases in India so far.

26/11: Need for a Commission of Inquiry

My fourth demand is indeed a reiteration of my earlier demand, made in the session of Parliament held after 26/11. It is that the Centre must set up a high-level judicial commission to probe all aspects of 26/11, in the same way that the US government set up a Commission to inquire 9/11.

My demand stems from the news last week that the government of Maharashtra, which had come in for sharp criticism during the 26/11 attack, has got a clean chit from the Ram Pradhan committee. The two-member committee appointed by the state government for inquiry of lapses during 26/11 has blamed the central government for intelligence failure.

I am quoting here a news report in The Times of India of 28 May 2009, titled 'Centre to blame for 26/11 lapse: Panel'. It reads: "During his visit to Mumbai after the terror attack, Union home minister P C Chidambaram apologized to the citizens of the state, this itself indicated lapses from the Union government," said R D Pradhan, after submitting the 100-page report to chief minister Ashok Chavan."

Madame Speaker, there are many things questionable about the findings of this committee. Firstly, here was an episode that led to the sacking of the state's chief minister and deputy chief minister, who was also the home minister. And yet, the committee gives a clean chit to the state government.

Secondly, the committee seems to have made shoddy job of its

mandate. Indeed, both the terms of reference as well as the actual functioning of the committee, left a lot to be desired. Let me again quote from the Times of India report:

"The probe panel was an administrative committee and not a judicial panel, hence many issues that are subjudice were not investigated, Pradhan said and added, "The panel was approached by many of the non-official persons, *but we decided not to meet any of these people. The report does not include version of the non-officials*, but is based on the enquiry conducted of over 50 police officers (ranging from constable to senior IPS officers)."

"Post attack many people including politicians from the ruling and opposition parties had criticized the functioning of the police control room. However after the probe, the conclusion of the panel was surprising."

Another report, in DNA of 28 May 2009, states that Vinita Kamte, wife of slain police officer Ashok Kamte who was killed during the 26/11 terror attacks, expressed disappointment over the Ram Pradhan committee report which has given a clean chit to the Mumbai police and government.

According to the report, she wanted to depose before the committee but was not allowed to do so. She has also alleged that "certain portions of the call records of the police control room on November 26 were deleted".

This is a serious matter. There is strong suspicion among the people of Mumbai, Maharashtra and the rest of the country that the Pradhan Committee has done a "white wash" job to protect the Congress government in the state.

Hence, my fourth demand: The central government must set up a judicial commission to inquire into all aspects of 26/11 — the lapses at the state level as well as the central level. After all, many senior functionaries in the UPA government — Prime Minister, former Home Minister (who was asked to resign after 26/11), Defence Minister and the National Security Advisor — had spoken about the possibility of terrorists using the sea route to mount an attack.

The truth must come out. Accountability must be fixed. Moreover, the 26/11 Inquiry Commission, and the implementation of the measures that it would recommend, would help India minimize possible terrorist attacks on India in the future. At any rate, it will help us to be better prepared.

Mr. Prime Minister, do not think that I am raising this demand to score political points. The people of India, who have given your government a second term in spite of a weak record in fighting terrorism, expect this from you.

One Rank One Pension

Madame Speaker, I am happy to note that the President's Address, in Para 12, has talked about the issue of ONE RANK ONE PENSION for ex-servicemen. They have been demanding it for a long time. They even launched a prolonged agitation at Jantar Mantar. I had gone there to show my solidarity with their demand. Over 11,000 ex-Army personnel had returned their gallantry medals in protest.

The President's Address, however, does not give a firm commitment that the Government would accept this demand. The wording is very vague and cannot satisfy ex-servicemen.

I demand that the Prime Minister, when he replies to this debate, give a firm commitment that his government would implement ONE RANK ONE PENSION within the first 100 days.

DEVELOPMENT ISSUES

Girls' education: Why not implement Ladli Laxmi Yojana?

Madame Speaker, After Security, I'll turn to some Development-related issues.

I am pleased to know that the Respected Rashtrapati's Address shows concern about female literacy in the country. It rightly laments in Para 21 that "While male literacy went up to over 75% in the last census and is expected to be higher now, female literacy was only 54% in 2001."

The Address goes to say: "My Government will recast the National Literacy Mission as a National Mission for Female Literacy to make every woman literate in the next five years."

I welcome this commitment. However, I would have been happy if the Address had also said that the Central Government would work closely with, and fully support the existing initiatives of, all the State Governments in achieving this mission.

Why do I say this? I say so because, unfortunately, a certain political culture has grown in this country in which the Centre thinks that it should take the credit for everything, and if something good is being done by a state government run by an opposition party, it should be ignored.

Take, for example, the Ladli Laxmi Yojana being implemented by the BJP government in Madhya Pradesh. Its specific objective is to promote female literacy and education. It provides financial assistance to the girl child at regular intervals and, when she completes 12th standard, the scheme gives her 1,20,000 rupees. To the best of my knowledge, it is the only one of its kind. And it has achieved significant success.

I would like the Prime Minister to adopt this scheme for nationwide implementation. As I said earlier, there is no copyright of my party for this

scheme. After all, the Sarva Shiksha Abhiyan, which has been mentioned in the President's Address, was launched by the NDA government. Similarly, there are several good schemes launched by the Congress governments in the past.

If the nation is to progress faster, we should discard the mental habit of trying to score political points in the area of implementation of development schemes.

Full support to Women's Reservation Bill

Madame Speaker, While on the point of women's all-round development empowerment, let me state that my party will fully support the bill on women's reservation in Parliament and State Legislatures, as and when the government brings it forward.

This bill is awaiting passage for a long, long time.

I guess that perhaps it was waiting for the 15th Lok Sabha when a woman would become the Speaker!

IT literacy

Madame Speaker, On the issue of literacy, let me make another important point. Today in the 21st century, it is not enough for a person, man or woman, to be simply literate. Every Indian, especially girls and boys belonging to the new generation, must also become IT LITERATE.

My party, in its IT Vision Document — and I am placing it on the table of the House — has developed a comprehensive vision of how IT and the Internet can assist in India's all-round transformation. A specific point in it is about how we can create as many 1.2 crore IT-enabled employment opportunities in rural India alone.

I strongly believe that the INTERNET is the third greatest invention of mankind, after the Wheel and Electricity. Its benefits must reach every Indian. To begin with, access to the Internet in Indian languages, and Internet-based education at all levels, including primary and secondary levels, should be our goal to be reached in five years.

MULTI-PUPORSE NATIONAL IDENTITY CARD

Another point is about the introduction of a MULTI-PUPORSE NATIONAL IDENTITY CARD. The President's Address, in Para 13, talks about a "UNIQUE IDENTITY CARD" for each citizen in three years. I would urge that it should not only be UNIQUE, but also MULTI-PURPOSE.

I do not have to belabour this point. Today a citizen has a voter ID card, ration card, driving license, PAN card, etc. Why can't we have a single MULTI-PUPORSE NATIONAL IDENTITY CARD?

Making India hunger-free: Disturbing UNICEF Report

Madame Speaker, I am sure everyone in this House will agree that the focus of all our efforts in development should be ANTYODAYA – development of the Last Man in the queue. This means that the poor, belonging to all communities, should have the first claim on the nation's budgetary resources.

Whether India's GDP grows at 7 % 9% is less important than whether the benefits of growth reach the poorest Indians or not. In this context, I was most disturbed by media reports this week that, according to a recent UNICEF report, "the number of hungry in India increased from 209.5 million in 2004-06 to 230 million by end of 2007-08"

Clearly, both the Central and State governments have to redouble their efforts to end abject poverty, especially hunger, in our country.

Bringing Indian wealth stashed away in Swiss banks

Madame Speaker, An important issue came up during the recent election campaign — that of the enormous Indian wealth stashed away in Swiss banks and other tax havens around the world. Estimates vary, but it is generally regarded that the amount is quite substantial.

I had myself given a lot of prominence to this issue in my campaign. I must mention here that the JD(U), CPI(M) and other parties also had raised this issue.

The Prime Minister's initial response was dismissive. However, the government itself submitted an affidavit in the Supreme Court confirming that it is a non-trivial matter and that it is seized of the matter. The affidavit also mentioned that the IT department had raised a demand of Rs. 78,000 crore against an alleged hawala dealer based in Pune.

As the issue gained momentum, even the Prime Minister stated in his interview to The Times of India on 25 April that he would include the matter of bringing back the black money salted away in tax havens abroad in his 100-day Action Plan.

I am surprised to see that it is not there in the 100-day action plan mentioned in the President's Address.

The people of India want this money back, because it belongs to the nation and must be used for the nation's development. I would like to know, and the entire country would like to know, from the Prime Minister what his government is going to do in this matter.

No mention of corruption in the Address

Madame Speaker, I am pained to see that the government's future agenda of governance is eloquently silent on the issue of fighting

CORRUPTION. Indeed, the word "corruption" does not figure anywhere in the President's Address.

It does not figure even in Para 31, which talks about "reform of governance for effective delivery of public services".

How can governance be reformed if the cancer of corruption is not even recognized and no political will shown to cure it?

The Congress party and the government are today in a state of euphoria over their electoral victory. Perhaps they think that corruption is not an issue at all.

But I would like to advise and warn the Prime Minister and the leadership of the Congress to look at what happened to Rajiv Gandhi's government. He had won over 400 seats in the Lok Sabha for his party in 1984. Within two years, the most famous and politically explosive scandal of corruption in India's history broke out. It badly enfeebled the government and ultimately caused its downfall in 1989.

The entire country knows how the Bofors scandal was covered up. Some of the brazen cover-up actions, in terms of helping the main accused in the scandal, were taken up by the previous UPA government. Some shocking revelations came even as the election campaign was underway.

I do not want to go into all that today. The people of India know everything.

Let not the victory of the Congress be interpreted in a such a manner as to think that the people have given a clean chit to the Congress or that they think that they are going to keep quiet if action is not taken against corruption at high and low places.

Above all, all talk of GOOD GOVERNANCE REFORM is meaningless without a resolve to fight corruption. The Prime Minister's personal reputation is at stake. He should prove that he is a strong Prime Minister by taking stringent action to eliminate corruption in his government.

Some foreign policy issues

Madame Speaker, I shall conclude by making a few remarks on foreign policy matters mentioned in the President's Address.

India's foreign policy must regain its central focus on our neighbourhood. Recent happenings in our immediate neighbourhood are a matter of concern.

Sri Lanka

The government of Sri Lanka has finally overcome the challenge of the LTTE. But the manner in which the civilian Tamil population was made to suffer is a matter that has shocked the conscience of the international community. India must continue to stand by the democratic rights and

aspirations of the ethnic Tamil population in Sri Lanka. No durable solution to the ethnic issue is possible without recognizing and delivering justice and dignity to the Tamil people in the country.

Nepal

There has been a change of government in Nepal. I welcome this development. The Maoists' anti-India campaign was evident even in the recent developments in Nepal.

Let us wish the new Prime Minister, Shri Madhav Nepal, and his government success in dealing with the challenges facing the country. On our part, India must work to regain the strength of the traditional ties between our two countries.

Bangladesh

I am disappointed to see that there is no mention in the President's Address of the problem of illegal Bangladeshi immigrants in Assam and elsewhere in the country. India must take up this issue with Bangladesh. First, the government must do what it has been asked by the Supreme Court to do.

China

India should work for normalization of relations with China. There should be no let-up in these efforts. However, it is of utmost importance to ensure that India does not convey, even inadvertently, the impression of bending over backwards to please China.

Some recent reports about further Chinese assistance to Pakistan's nuclear programme are worrisome. China also continues to rake up the Arunachal Pradesh issue. The people of India expect the government to be firm in these matters.■

जिम्मेदारी से निभाएंगे प्रहरी की भूमिका

& Jherh l"kek Lojkt

उपाध्यक्ष जी, सुश्री गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा निरंतर जारी है। हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय आडवाणी जी ने चर्चा की शुरुआत करते हुये इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया और सरकार से कुछ अपेक्षायें भी कीं और सरकार के सामने अपनी मांगें भी रखीं।

मैं अभिभाषण के कुछ बिन्दुओं पर चर्चा शुरु करने से पहले डा. गिरिजा व्यास द्वारा चर्चा के प्रारंभिक वक्तव्य में कही गई कुछ बातों का उत्तर देना चाहूंगी। डा. गिरिजा से मेरे स्नेहल संबंध हैं और मैं उनकी योग्यता का बहुत सम्मान करती हूं। पर पता नहीं, उस दिन वह कुछ नाराज़ दिखीं। नाराज थीं या मजबूरी थी, यह वह स्वयं जानती हैं। मैं गिरिजा जी से इतना ही कहना चाहती हूं कि शपथ समारोह के दिन मेरी आंखें टी.वी. पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें खोज रही थीं परन्तु वह दिखाई नही दीं। इससे मुझे दुख भी हुआ मगर वहां का गुस्सा हम पर क्यों निकाला? इन्होंने तो इतना तक ऐलान कर दिया और वह भी अब के लिये नहीं बल्कि सदा के लिये। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इलैक्शन में बी.जे.पी. के ''सो काल्ड उसूलों'' के सवाल का जवाब है, "India Shining" का नारा लगाने वाली पार्टी की इतिश्री हो गई और आगे एक वाक्य जोड़ दिया कि यह इतिश्री सदा के लिये हो गई।

उपाध्यक्ष जी, मैं डा. गिरिजा को बताना चाहतीं हूं कि लोकतंत्र में चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, यह लोकतंत्र की बुनियाद का नियम है लेकिन यहां किसी की इति नहीं होती है. न पार्टी स्तर पर और न व्यक्तिगत स्तर पर। वह खुद इस बात की साक्षी हैं कि वह 12वीं लोक सभा में हारीं, 13वीं लोक सभा में जीतकर आयीं लेकिन 14वीं लोक सभा में एक नये नितांत प्रत्याशी श्रीमती किरण माहेश्वरी से चुनाव हार गईं। अब 15वीं लोक सभा में वह चुनाव जीतकर आयी हैं। मैं पार्टी स्तर पर एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि 1977 में अमृतसर से लेकर कोलकाता तक इन्दिरा गांधी का सफाया हो गया था जिस पर बहुत से समीक्षकों ने कहा कि कांग्रेस की इतिश्री हो गई है लेकिन मात्र ढाई साल में इन्दिरा जी उसी धमक से साथ लौटी थीं। सन् 1984 में स्व. राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थीं और हमारी पार्टी सिर्फ दो सीटें ले पायी। पांच वर्ष बाद जब चुनाव आये तो हमारी पार्टी 43 गुना होकर उभरी थी। आज तो हम 116 पर हैं। मैं 1999 के चुनाव की याद दिला दूं कि उस समय कांग्रेस सिर्फ 114 सीटें जीतकर आयी थी और बीजेपी की 116 की संख्या है जो 114

से ज्यादा है। अगर 1999 में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर 2004 के चुनाव में केन्द्र में सरकार बना सकती है तो 116 सीटें जीतने वाली पार्टी की इतिश्री कैसे हो गई?

उपाध्यक्ष जी, वास्तव में डा. गिरिजा साहित्यकार हैं और साहित्य में हर कहानी की इतिश्री होती है, और हर उपन्यास में ऐसा होता है। लेकिन मैं राजनेत्री डा. गिरिजा को बताना चाहूंगी कि राजनीति साहित्य नहीं होता है। राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं। किसी लड़ाई की इतिश्री तब होती है जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे लेकिन हम मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, हम मैदान में डटे हुये हैं और इसी पराजय में से हम विजय की राह निकालेंगे, आज मैं इसका ऐलान करती हूं।

महोदय, अब मैं अभिभाषण के प्रथम बिंदु पर आती हूं। महामहिम, राष्ट्रपति महोदया ने प्रारम्भ में ही पहले पैराग्राफ में सबको बधाई दी, पांच पैराग्राफ तक वो अलग–अलग बधाई देती रहीं और छठे पैराग्राफ से उन्होंने सरकार का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह इसी समावेशी नीति का परिणाम है। सरकार यह मानती है कि वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण जीती है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जब राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो वे इस विश्लेषण को सही नहीं पाएंगे। नीतियों का जनादेश तब होता जब सारे नीति–निर्धारक चुनावी समर में जनादेश प्राप्त करने के लिए उतरे होते।

महोदय, नीति–निर्धारण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पांच मंत्री तो चुनावी समर में उतरे ही नहीं और जो उतरे उनमें से बहुत हार गये। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़े, रक्षा मंत्री चुनाव नहीं लड़े, शिक्षा मंत्री यानी एचआरडी मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़े। साढ़े चार साल तक गृह विभाग संभालने वाले गृह मंत्री चुनाव नहीं लड़े और साढ़े चार साल तक वित्त विभाग संभालने वाले वर्तमान गृह मंत्री चुनाव हारते–हारते री–काउंट में चुनाव जीते। इनके कई प्रमुख मंत्री चुनाव हार गये। श्री मणिशंकर अय्यर चुनाव हारे, श्री शंकर सुमन देव चुनाव हारे, श्री रामविलास पासवान चुनाव हारे, श्री रामदौस चुनाव हारे, श्री ए.आर.अंतुले चुनाव हारे, श्री शंकर सिंह वाघेला चुनाव हारे, श्री नारायण सिंह राठौर चुनाव हारे, श्रीमती रेणुका चौधरी चुनाव हारीं। मेरे पास सूची है, आपके 21 मंत्री चुनाव नहीं लड़े हैं और 16 मंत्री चुनाव हार गये हैं। क्या आप इसे नीतियों का जनादेश कहेंगे?

महोदय, एक दूसरी बात कही गयी है कि यह सेक्लुरिज्म पर जनादेश है, पंथनिरपेक्षता पर जनादेश है, लेकिन यह भी सही नहीं है। सेक्लुरिज्म के सारे पुरोधा ढह गये हैं। सेक्लुरिज्म के सबसे बड़े पैरोकार वामपंथी, सीपीएम वाले 43 सीटों से सिमटकर 16 सीटों पर खड़े हो गए हैं। सीपीआई 10 सीट से घटकर 4 सीट पर आ गयी है। सेक्लुरिज्म के दूसरे आलम्बरदार, मेरे अत्यंत स्नेही भाई श्री लालू प्रसाद यादव 23 सीट से घटकर 4 सीट पर आ गये हैं। श्री मुलायम सिंह यादव 38 सीट से घटकर 22 सीट पर आ गये हैं। श्री वासुदेव जी अभी कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, नीतियों की बात मैंने कर दी हैं। कार्यक्रमों का

पूरा पर्दाफाश कर रहे थे, पूरी पोल खोल रहे थे कि क्या लक्ष्य था, क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया? मैं यह कहना चाहती हूं कि यह नीतियों की विजय नहीं हैं, यह परिस्थितियों की विजय है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गयीं और आप चुनाव जीत गये। यह भी सच है कि जनादेश आपको ही मिला है, जीत आपकी ही हुई है, सरकार चलाने का जनादेश आपको मिला है। आप शौक से सरकार चलाइये, अच्छी तरह सरकार चलाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे मेरे बहुत स्नेही मित्र हैं। मैं एक बहुचर्चित गीत की एक छोटी सी पंक्ति आपके जेहन में डालना चाहती हूं और अगर सरकार चलाते वक्त वह बात आप याद रखेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। ''पेश आएगी हमारी जरूरत कभी–कभी।'' अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर सरकार अच्छी तरह से चला सकेंगे।

महोदय, गिरिजा जी ने उसके बाद यह कहा कि मैंने एक बयान में यह कहा है कि सरकार ने हमारा एजेंडा ले लिया है और उसे अभिभाषण में शामिल कर लिया है। यह सच है, मैंने यह बात कही है, लेकिन मैनें यह बात शिकायती स्वर में नहीं कही है, यह बात मैंने खुशी से कही है। उस दिन श्री आडवाणी जी ने कहा था कि विकास और कल्याण के कार्यो में श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी हुई कि जो काम हम करना चाहते थे, उन्हें आपने करने का वादा किया है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह एजेंडा हमारा नहीं था। मैं पूछना चाहती हूं कि स्विस बैंक से काला धन देश में वापस लाने का एजेंडा किसने रखा। निःसंदेह आडवाणी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, एक रैंक एक पेंशन की बात भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा–पत्र में थी। स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत आरक्षण करने का काम एक एनडीए शासित और चार भाजपा शासित राज्य सरकारों ने किया।

मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड और एनडीए शासित बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके विधेयक का इंतजार नहीं किया, जो कि आप आज अपनाने वाले हैं। उन्होंने अपने तौर पर 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। कई जगह तो चुनाव 50 प्रतिशत पर हुए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। यह एजेण्डा किसने सैट किया, भारतीय जनता पार्टी ने।

आपने तीन रूपये किलो चावल खिलाने की बात कही। लेकिन वर्ष 2007 से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री 35 किलो चावल तीन रूपये प्रति किलो पर खिला रहे हैं। मुझे दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि वर्ष 2007 में जब डॉ. रमन सिंह ने अपने यहां के गरीब परिवारों को तीन रूपये किलो के हिसाब से चावल खिलाने की बात कही, उस समय छत्तीसगढ के चावल का कोटा 61 हजार मीट्रिक टन था। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा यह निर्णय लेने के बाद केन्द्र सरकार ने कहा कि यदि तीन रूपये खिलाना है तो बाजार से खरीदकर खिलाओ। उन्होंने कोटा काटकर 953 मीट्रिक टन कर दिया। कोई सोच सकता है 97 प्रतिशत की कटौती? 60 हजार मीट्रिक टन चावल आपने उनका काट लिया, मात्र 953 मीट्रिक टन दिया। लेकिन मैं डॉ. रमन सिंह को शाबासी देना चाहती हूं कि उन्होंने आपके दबाव के बाद भी अपना पैर पीछे नहीं हटाया और एक हजार करोड़ रूपया अपने बजट से निकालकर अपने संकल्प को पूरा किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वे छत्तीसगढ के 37

लाख लोगों को तीन रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिमाह चावल खिला रहे हैं और जब आप तीन रूपये करने जा रहे हैं तो उन्होंने तय किया है कि अन्त्योदय के आठ लाख परिवारों को वह एक रूपये किलो के हिसाब से खिलाएंगे बाकी के 29 लाख परिवारों को दो रूपये किलो खिलाएंगे। आप अपने भाषण में कह रही थीं कि कांग्रेस कैसे किसी को भूखा देख सकती है?

मैं तो इस बात का जवाब दे रही हूं कि कांग्रेस लोगों को भूखा नहीं रख सकती है। इसलिए छत्तीसगढ ने जो किया, वह बता रही हूं, इसके साथ ही साथ आपने क्या किया, वह भी बता रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी योजनाओं को चलाने के समय शासक दल का नामपट्ट देखकर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं मध्य प्रदेश से चुनकर आयी हूं और वह मध्य प्रदेश भेदभाव भुगत रहा है। 31 लाख बीपीएल परिवारों की सूची हमने आपको भेजी है, लेकिन केन्द्र हमें उनका खाद्यान्न नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इन योजनाओं को शुरू करने से पहले आप बीपीएल के मानदण्ड बदलिए। जब एक साथ जीवनयापन करने वाले दो पड़ोसी एक साथ रहते हैं, एक को सरकारी सहायता मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है, तो उसके मन में जो पीड़ा होती है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीपीएल के मानदण्ड नये तरीके से तय कीजिए। नये तरीके से सूचियां बनवाइए, उसके बाद आप इस तरह की योजनाएं चालू करिए, यह मेरा आपको सुझाव है।

मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही थी। केवल खाद्यान्न की बात नहीं है। आपने हमारी कोयले की आपूर्ति काट ली। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। पानी नहीं बरसा है। हमारी पनबिजली परियोजनाएं लगभग ठप्प पड़ी हैं। 22 सौ मेगावाट बिजली हम पानी से बनाते थे, हम आज केवल तीन सौ मेगावाट बना रहे हैं। आपने हमारी अनावंटित कोटे की बिजली भी काट दी और थर्मल पावर प्लांट जिन्हें 17 लाख मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, उन्हें आप 11 लाख मीट्रिक टन दे रहे हैं।

यहां बार–बार आकर मुख्य मंत्री मिलते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। अभी आपने लेटेस्ट 4 मई को पत्र लिख कर कहा कि कोयला आयात कर लीजिए। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हमारे यहां कोयला उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें हैं। वहां से व्यापारियों को बेचने के लिए आप कोयला देते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री को कहते हैं कि कोयला आयात कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जब विकास और कल्याण की ये योजनाएं चलें, तो तमाम राज्य, चाहे वहां किसी का भी शासन हो, क्योंकि पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपने बिहार को दी गई जो फ्लड राहत राशि थी, वह वापस ले ली।

कल, उड़ीसा की तरफ से श्री भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे कि उड़ीसा को दी गई राहत राशि आपने वापस मांग ली। जब सारे गैर–कांग्रेसी राज्य यहां आकर रोना रोते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, तो लगता है कि केन्द्र की दृष्टि निपक्ष नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि योजनाएं तो आप जरूर चलाइए, लेकिन दृष्टि निपक्ष रखकर चलाइए।

महोदय, यहीं मुझे एक और शिकायत दर्ज करनी है। राष्ट्रपति अभिभाषण के पैराग्राफ 19 में स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं का जिक्र किया है। मैंने आंखें

गड़ा–गड़ा कर देखा, उस दिन कान लगा–लगा कर सुना कि कम से कम इसमें उन छः एम्स के निर्माण कार्य की बात जरूर होगी, जिन्हें मैं सन् 2003 में स्वी. त कर के गई थी, लेकिन मुझे दुख हुआ। वे न तो आपके पैराग्राफ 19 में है और न वे आपके 100 दिनों के एक्शन–प्लान में हैं। यहां प्रणब दा बैठे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि सन् 2003 में, वह योजना मैं लेकर आई थी। मैं अपने लिए नहीं लाई थी। मैंने एक निपक्ष दृष्टि रखी थी। मैंने डायरैक्टर से डेटा मंगवाया था कि कहां–कहां से लोग एम्स में आते हैं। इस देश में 56 साल पहले एक एम्स बना था। उसके बाद से कितनी जनसंख्या बढ गई, लेकिन एम्स में बढोत्तरी नहीं हुई। जब डेटा आया, तो डेटा के आधार पर मैंने राज्य चुने। यह नहीं देखा था कि वहां किस का राज्य है। छः में से चार राज्य कांग्रेस शासित थे, एक राज्य आर.जे.डी. शासित था और केवल एक राज्य एन.डी.ए. शासित था। बी. जे.पी. शासित एक भी राज्य उसमें नहीं था। तब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, छत्तीसगढ में कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन था और बिहार में लालू जी का शासन था। केवल उड़ीसा में बीजू जनता दल का शासन था। एक भी बी.जे.पी. शासित राज्य नहीं था। चूंकि शिक्षा की दृष्टि से वे पिछड़े राज्य थे, इसीलिए उन्हें चुना। अपने समय में तब केवल 10 महीने का कार्यकाल था। अपने कार्यालय में एक घंटा इन एम्स को बनाने में समर्पित कर दिया था। इन 10 महीनों में छः मुख्यमंत्रियों से जमीनें ले लीं, छः के शिलान्यास करा दिए, केवल वोट ऑन एकाउंट था, उसमें भी बजट हैड बनवा दिया और छः करोड़ रुपए उनकी चार–दीवारी बनाने के लिए रख दिया। यह सारा काम 10 महीने में पूरा कर के दे दिया। आपने पांच साल निकाल दिए। उन चार–दीवारी में से कोई एक ईंट तो निकाल कर ले गया होगा, लेकिन उन छः एम्स पर आपने एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया।

महोदय, मैंने छः एम्स को अपग्रेड करने का काम भी किया था। दोनों सदनों में, हर सत्र में, इस विषय को एक न एक सांसद जरूर उठाता रहा था। श्री लाल सिंह, जम्मू कश्मीर के यहां बैठे हैं। आप हर बार इस विषय को उठाते थे, क्योंकि इनके यहां भी एम्स को मैंने अपग्रेड किया था। दोनों सदनों में, कभी ध्यानाकर्षण आता था, कभी प्रश्न आता था। हर बार स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि बस, अब हम निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं, लेकिन पांच वर्ष बीत गए और निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। एक पुण्य का कार्य, श्री वी. नारायणसामी ने जरूर कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्री को हराकर, आज वे पुदुचेरी से सांसद बनकर यहां आ गए हैं। इसलिए मैं श्री नारायणसामी को बधाई देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष जी, इससे आगे, मैं एक और चूक की बात आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं। सरकार ने अभिभाण के पैराग्राफ 25 में महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने की बात कही है। इन्होंने तीन प्राथमिकताएं रखी हैं– महिलाओं की शिक्षा, जिसे ये साक्षरता कह रहे हैं, महिलाओं की नौकरी और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण। ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रणब दा, आप एक बहुत जरूरी बात भूल गए। आपने शिक्षा की समस्या याद रखी, आपने नौकरी की समस्या भी याद रखी और आपने राजनीतिक सशक्तीकरण की समस्या भी याद रखी, लेकिन आप उसके जन्म की समस्या भूल गए।

अगर जन्मेगी नहीं तो शिक्षित कैसे होगी, अगर जन्मेगी नहीं तो नौकरी कैसे प्राप्त करेगी, अगर जन्मेगी नहीं तो चुनकर कैसे आएगी। आज तो उसके जन्म

के सामने ही प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। भ्रूण हत्या देश में इतना बड़ा अपराध बन गया है कि कई बार तो मैं हैरान होती हूं कि जो देश वर्ष में दो–दो बार कन्या पूजन करता है, वह अपनी बेटी को गर्भ में मारने का पाप कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपसे यह चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि नीयतन आपने ऐसा किया है, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की भूल सुधारने का भी काम करते हैं। तीन चीजें जो आपने रखी हैं, उसमें भ्रूण हत्या आप जरूर डालने का काम करिये।

एक बात तो उस दिन आडवाणी जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की कही थी। मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना चली है, वह भ्रूण हत्या को सबसे पहले रोकती है, क्योंकि वह पैसा जन्म के समय दिया जाता है। वह एक ऐसी योजना है, जो लड़की के जन्म से लेकर, उसकी शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री से कहिये, उस योजना का मसौदा मंगवाकर देखें। अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो करें, कोई सुधार करना है तो करें, लेकिन जब तक आप बच्ची के जन्म की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये बाकी तीनों चीजें भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना को मंगवाकर उसको पूरे देश में लागू करने का काम करिये। वह भ्रूण हत्या को रोकेगी और महिला साक्षरता को बढ़ाएगी।

आपने महिला आरक्षण की बात की है, एक तरफ महिलाओं में उससे बहुत ज्यादा उत्साह आया है। दूसरी तरफ बवाल भी मचा है, क्यों शरद भाई? लेकिन शरद भाई, बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोग यह सोच रहे हैं कि आपने तीन महीने में यह बिल पारित कराने की बात कही है। ऐसा नहीं है। इसमें एक पेज है और वह पेज लिखा गया है, वह कोई नहीं पढ रहा है। पहला वाक्य पढक़र मेरी सरकार अगले सौ दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी। राज्य विधान मंडलों में और संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए कदम उठाएगी, यानी प्रधानमंत्री अगर सभी दलों की सर्वानुमति बनाने के लिए एक मीटिंग बुला लेंगे तो कदम उठ गया। यह वायदा पूरा हो गया। कदम उठाएगी, बिल पारित नहीं कराएगी तो आप क्यों जहर खाने की बात कर रहे हैं।

गिरिजा जी, इससे तो कहीं बड़ा कदम हम उठा चुके। जहां तक प्रधानमंत्री के स्तर की मीटिंग की बात है, अटल जी के स्तर पर तीन मीटिंग हुईं। उसके बाद पीठासीन अध्यक्ष उस समय मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने यह काम अपने सिर पर लिया। उनके स्तर पर मीटिंग हुई, उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आये तो उनके स्तर पर मीटिंग हुई। जहां तक कदम उठाने की बात है, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैंने तो वह कदम उठा लिया था कि बिल को चर्चा के लिए कार्य–सूची में लगा दिया था। आप इससे बड़ा क्या कदम उठाएंगे, कार्य–सूची में लगा दिया था, लेकिन उस दिन भी बिल के विरोधियों ने यह कहा कि जब तक यह कार्य–सूची से निकलेगा नहीं, हम कार्रवाई चलने ही नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। आप तो ऐसे हो गये, लेकिन शायद मीडिया ने भी इसको नहीं पढ़ा। तीन महीने में महिला बिल पारित हो जायेगा, लेकिन तीन महीने में महिला बिल पारित होने का वायदा ही नहीं है, कदम उठाने का वायदा है। मैंने अंग्रेजी का भी मंगाकर पढ़ा, उसमें भी यही है, Government will initate step

जैसा मैंने कहा, एक मीटिंग होगी। वह कदम उठ जायेगा, इनका वायदा पूरा हो जायेगा। लेकिन महिला आरक्षण कब होगा, इसलिए प्रणव दॉ, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप समयावधि तय करिये। बिल पारित कब करेंगे, जब वह समयावधि तय होगी, तब मैं कहूंगी कि महिलाएं उत्साहित हों और कहें कि महिला आरक्षण बिल पारित होगा, अभी तो केवल कदम उठाने की बात कही गई है।

अब मैं अभिभाषण के पैरा 42 की बात करना चाहती हूं, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान सम्बन्धों की बात कही है। यह पैराग्राफ भारत पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को लेकर समाप्त हो गया।

जो विषय आज प्रासंगिक है, उससे यह अभिभाषण अनछुआ रहा। रोज समाचार आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी संभावना को देखते हुए अटल जी ने अपने कार्यकाल में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का कार्य किया था और पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो कुछ हमने अटल जी के राज में हासिल किया था, भारत–अमेरिका परमाणु समझौते के रास्ते, उसे हमने खो दिया। हमने अपने ऊपर यह पाबंदी लगा ली कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे, अगर यह करेंगे, तो समझौता टूट जाएगा। इसलिए मैं आज एक प्रश्न करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री उत्तर दें कि यह जो परमाणु क्षमता में वृद्धि पाकिस्तान कर रहा है, इससे निपटने के लिए हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं?

हमने अमेरिका से उसके बदले में कुछ लिया नहीं था कि अगर हम उस वाल्युएंट्री मोरेटोरियम को छोड़ते तो कुछ वापस करना पड़ता। आप उसका साथ बांधकर देकर आए हैं। आपने कहा है कि अगर यह परमाणु परीक्षण हम करेंगे, तो यह समझौता टूट जाएगा, ताकि उसमें जो कुछ तब तक आया हुआ होगा, वह वापस हो जाएगा। दोनों चीजें समानान्तर नहीं हैं। हमने वाल्युएंट्री मोरेटोरियम की बात की थी, आपने समझौते के साथ उसको जोड़ने की बात की है। इसलिए आज देश जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि करता है, तो भारत उसका मुकाबला कैसे करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पाकिस्तान के बाद इसी पैराग्राफ में श्रीलंका के तमिलों की बात आयी है। जहां तक श्रीलंका का सवाल है, मैं बहुत साफ कह देना चाहती हूं कि हम श्रीलंका की सार्वभौमिकता के पक्षधर हैं। वहां किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के विरोधी हैं। लेकिन हमारे तमिल भाइयों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरूद्ध क्या हम आंखें मूंदकर बैठ सकते हैं? अभी डीएमके के इलेंगोवन जी बोल रहे थे कि जब ज्यूस की हत्या हुयी, तो पूरा का पूरा विश्व उठ खड़ा हुआ, लेकिन नो–वार जोन में हमारे तमिल भाइयों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तब कोई बोल नहीं रहा है। जब हम अपनी तमिल महिलाओं को रोते–बिलखते देखते हैं, तमिल बच्चों को दूध के लिए कराहते और तड़पते देखते हैं, तो हमारा खून खौलता है। सिर्फ इसलिए कि वे सरहद पार रहते हैं। क्या हम उनके दुख और दर्द को भूल जाएंगे? खून एक है। खून उबाल खाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, तमिल कविताओं का एक संग्रह है – नन्नेरी। उसमें बहुत प्रसिद्ध कवियों की कविताएं लिखी हुयी हैं। उसमें से चार पक्तियां पढक़र मैं आपको बताना चाहती हूं। चिदंबरम जी तो इसे समझ ही जाएंगे, बाद में मैं उसका अर्थ

बता दूंगी। नन्नेरी में लिखा है,

é ijh;oj reukbl iky fijj ukbl dM mYye]
,jhbu b>M vkoj ,U?kk Fkjh b>kb]
eM fif.k;ky o:èke ihj m:lib
dM d>kye d.kA é

इसका अर्थ है कि शरीर के किसी भी भाग में अगर घाव होता है, पीड़ा होती है, तो आंसू आंख बहाती है। इसीलिए अगर मानवता के ऊपर, हमारी फैलो ह्यूमन बींग्स के ऊपर दुनिया में कहीं भी, भले ही सरहद पार अगर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अच्छे लोग उसकी चिंता करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपने इसमें लिखा है, लेकिन वह नाकाफी है। हमारी तरफ से वहां लोगों को जाना चाहिए। उनकी पीड़ा देखनी चाहिए। भारत उनका पड़ोसी देश है, हम अपने उन लोगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। उनके संकट में जितनी कमी करा सकते हैं, उनके कष्ट में जितनी कमी करा सकते हैं, वह करने का काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 45 में इंडियन डायसपोरा की बात है, प्रवासी भारतीयों की बात है, लेकिन मुझे बहुत बार हैरानी होती है कि हम एक तरफ तो प्रवासी भारतीयों को अपना अघोषित राजदूत कहते हैं, इतना माथा ऊंचा किया है उन्होंने हमारा, अमेरिका जैसे बड़े देश में भारतीय हमें गौरवान्वित कर रहे हैं।

लेकिन आए दिन प्रवासी भारतीयों के कष्ट की खबरें आती रहती हैं। कभी मलेशिया में भारतीयों के साथ मार–पीट की जाती है, कभी कज़ाकिस्तान में इस्कॉन का मंदिर तोड़ा जाता है, कभी फ्रांस में सिख बच्चों को स्कूल में जाने पर पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिखों पर जजिया लगाया जाता है और अब तो यह कहा जा रहा है कि अन्य धर्मावलंबियों से भी जजिया लिया जाएगा। आस्ट्रेलिया में तो आजकल हद हो रखी है। सिर में स्क्रियू ड्राइवर डालकर घायल किए हुए उस बच्चे की तस्वीर जब टेलीविजन पर दिखाई जाती है तो रूह कांप उठती है। आज भी अखबार भरे पड़े हैं कि कल एक भारतीय छात्र की कार जला दी गई। मुझे दुख तब होता है जब इस सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे मिशन में स्टाफ ही बहुत कम है, केवल आठ लोग हैं। उसके ऊपर फिर वे दो–दो दोष देते हैं। वे दोनों मंत्री यहां बैठे हैं जिन पर वे दोष देते हैं। वे कहते हैं कि वित्त मंत्री जी के दवाब में विदेश मंत्री जी ने स्टाफ कम कर दिया और अब चूंकि विदेश मंत्री ही वित्त मंत्री बन गए हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपना फैसला बदलें। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि स्टाफ कम है या ज्यादा, इससे किसी को क्या मतलब। फैसला किसने बदला, क्या बदला, क्यों बदला, कैसे बदला, इससे हमें क्या सरोकार है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। देश यह चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप आठ के स्टाफ से करें या दस के स्टाफ से करें, आप बारह के स्टाफ से करें या चौबीस के स्टाफ से करें, स्टाफ बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन आप उन बच्चों को सुरक्षा मुहैया करवाइए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इतने बड़े–बड़े संकल्प का अभिभाषण और दूसरी तरफ मंत्रियों के इस तरह के असहाय जवाब, यह दोनों मेल नहीं खाते।

कल मैं मोइली जी का एक बयान पढ ऱ़ही थी – I can't do anything for corruption in Judiciary यह दोनों चीजें कैसे मेल खाएंगी। इस अभिभाषण

को पूरा करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, बहुत दृढता की जरूरत होगी। अगर मंत्रीगण इस तरह के असहायपूर्ण बयान देंगे, तो देशवासी क्या समझेंगे। इसीलिए उस दिन भी आडवाणी जी ने कहा था कि आस्ट्रेलिया में जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि बहुत युवा सांसदों का एक डेलीगेशन अगर आप यहां से भेजें, वे स्वयं वहां जाकर देखकर आएंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे देश से कोई हमें पूछने आया, कोई हमारी सुध लेने आया और उन्हें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है। मुझे लगता है कि इसे करने में कोई ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। हमें यह करना चाहिए।

अंतिम पैराग्राफ में राष्ट्रपति जी ने देश के युवजन की आशा और आकांक्षा की बात की है। बहुत अच्छा है। देश में बहुत युवा बयार बही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यह पहली बार नहीं हुआ जब देश का युवजन खड़ा हुआ है। इस देश ने जब–जब नाजुक मौका देखा है, युवजन ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी 23 वर्ष के भगत सिंह और 19 वर्ष के अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पर चढ गए थे। स्वतंत्र भारत में भी जब कांग्रेस का विघटन हुआ था, बड़ी उम्र के लोग कांग्रेस (ओ) में चले गए थे, तो कमान यंगस्टर्स ने संभाली थी और बहुत वर्षो तक वे भारत के राजनीतिक पटल पर छाए रहे थे। उसके बाद जब इस देश में इमरजैंसी लगी थी तो लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध भी इस देश में युवजन ने ही लड़ा था और एक बूढ़े के नेतृत्व में लड़ा था। तब भी यही युवा ऊर्जा सड़कों पर उभरी थी। उस आंदोलन की उपज आज भी इस ससंद में दिखाई देती है। प्रथम पंक्तियों पर बैठे हैं। भाई शरद यादव यहां बैठे हुए हैं। पहले जनता सांसद के रूप में चुनकर आए थे। शरद भाई की उम्र पच्चीस साल एक माह थी। पच्चीस साल एक माह की उम्र में ये जनता सांसद के रूप में इस सदन में जीतकर आए थे। उसी आंदोलन की उपज हैं। विभिन्न दलों में उस आंदोलन के लोग बैठे हैं, लेकिन भरपूर मात्रा मे यहां विद्यमान हैं। ये पच्चीस साल की उम्र में यहां सांसद बने थे और मैं पच्चीस वर्ष की उम्र में हरियाणा में केबिनेट की मंत्री बनी थी। असम का पूरा आंदोलन युवजनों का आंदोलन था। 25 से 30 वर्ष के लोग चुनकर आए थे और यह पहली बार नहीं है कि यहां युवा चुनकर आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, यहां योगी आदित्य नाथ बैठे हैं। 37 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए हैं। श्री अनंत हेगड़े पीछे बैठे हैं। 40 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए हैं। श्री अशोक अर्गल मेरे पीछे बैठे हैं। 40 वर्ष की उम्र है, पांचवी बार चुनकर आए हैं। यहां श्री अनंत कुमार बैठे हैं। 36 साल की उम्र में सबसे पहले चुनकर आए थे। श्री शाहनवाज़ हुसैन 36 साल की उम्र में केबिनेट के मंत्री बन गए थे। उपाध्यक्ष जी, अटल जी की केबिनेट में 11 मंत्री 50 वर्ष से कम की उम्र के थे।

मैं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के बारे में कह रही हूं, कोई एमओएस नहीं कह रही हूं। अब एमओएस तो बहुत हैं। अटल जी की कैबिनेट में 12 कैबिनेट मंत्री 50 से कम उम्र के थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आठ मुख्य मंत्री 50 से कम उम्र के बनाये गये। यहां अर्जुन मुंड़ा बैठे हुए हैं, वे 35 बरस की उम्र में मुख्य मंत्री बन गये थे, तो ये युवा बयार पहली बार नहीं बही। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस संसद में युवा सांसद जीतकर आये हैं।

मैं उन सबका ह्रदय से अभिनंदन करती हूं, क्योंकि जब वे भोले–भाले चेहरे मुझे दिखते हैं, तो जिंदगी में, मैं स्वयं पीछे पहुंच जाती हूं और मुझे अपना समय याद आ जाता है, जब मैं 25 बरस की उम्र में चुनकर गयी थी और कैबिनेट मंत्रालय का भार संभाला था। लेकिन मैं केवल उनका अभिनंदन नहीं करती, मैं उनको ढेरों–ढेरों शुभकामनाएं देती हूं कि जिन अपेक्षाओं से उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जीताकर भेजा है, वे उन अपेक्षाओं को पूरा करें। लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना होगा। हां, पवन भाई को देखकर मुझे याद आया, पवन भाई और मैं एक ही डिपार्टमैंट से पढ़े हैं, लेकिन वे एक साल मेरे सीनियर थे। वे उम्र में शायद मुझसे तीन साल बड़े हैं। तेरह साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बना दिया था और तेरह साल बाद इनकी पार्टी को याद आयी है और वह भी सीजनल मिनिस्ट्री देकर चूक गये हैं। चार महीने काम करेंगे और आठ महीने खाली बैठेंगे। प्रणब दा, कम से कम महकमा तो साथ में दिलवा दीजिए कि बारह महीने मेरा भाई काम कर सके। वह बहुत योग्य है, वह डिपार्टमैंट ही बहुत योग्य लोगों को निकालता है। कम से कम बारह महीने का मंत्रिमंडल तो इनका मिलता। आप इन्हें ऐसा मंत्रालय दीजिए जिससे ये बारह महीने काम कर सके।

उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यौवन बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता। अगर विलंब होता है, तो यौवन अधीर हो उठता है और उस अधीरता में खतरे का संकेत छिपा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर आयी है। सौ दिन में तस्वीर नहीं बदल सकती लेकिन तस्वीर बदलने की रूपरेखा तैयार हो सकती है। आप लोग रूपरेखा तैयार करिये, मैं अपनी ओर से आश्वासन देना चाहती हूं, आडवाणी जी ने आपको उस दिन आश्वासन दिया था, उस भावना से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है और हमें प्रहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे।

आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलायेंगे। आप नहीं करेंगे, हम आपको चेतायेंगे। आप गलत करेंगे, तो हम आपका विरोध करेंगे, लेकिन सौ दिन के बाद आपके अभिभाषण के उन बिन्दुओं को जरूर दर जरूर सत्य की कसौटी पर तोलने का काम करेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

Synopsis

One should not be in the race for taking credit of welfare and developmental works. I am happy to note that you have promised to do what we wanted to do. I am proud that the chief ministers of four BJP ruled States namely Madhya Pradesh, Chhattisgarh,

Rajasthan and Uttarakhand as also the NDA Governed State of Bihar have increased the quota of reservation for women from 33 to 50 per cent in their respective States.

The Government says that it would provide rice at the rate of Rs.3/- per kg. to the poor. But the Chief Minister of Chhattisgarh, a BJP ruled State has already been providing 35 kg. of rice at Rs.3/- per kg. since 2007.

The quota of rice for Chhattisgarh was 61 thousand metric tonnes that time but the Central Government has reduced it to a mere 953 metric tones i.e. a whopping reduction of 97 per cent. What I want to say is that there should be no discrimination against any state irrespective of whichever party's rule is there. But the Central Government has been discriminating against the state of Madhya Pradesh. A list of 31 crore BPL families has been sent by Madhya Pradesh but the Central Government is not providing foodgrains for them. Similarly, the supply of coal to Madhya Pradesh has also been curtailed. The State has been grappling with power crisis. There is draught like situation. The hydro power projects have almost come to standstill in the State.

I would like to state let the Government launch and run the schemes it likes, but they should be implemented in a fair and impartial manner. I am pained at the fact that neither in the Address nor in the action plan for 100

days, there is a mention of going ahead with the establishment of six AIIMSs. The AIIMS was set up in the country 58 years back. Thereafter, population increased multifold, but no subsequent AIIMS came up. In my tenure of 10 months, we had acquired land for them, we laid foundation stones for six AIIMSs and even earmarked Rs.6 crore under Budget head in the vote on account for the same to construct their boundary walls. However, even after five years of this Government's tenure no further work was done thereon. We even initiated action to upgrade the six existing AIIMSs.

Then, in the paragraph 25, there is a mention of creating equal opportunities for women. The Government propose to accord priorities to the literacy, employment and political empowerment of womenfolk. However, it fails to address the root cause relating to the very birth of female child. If a female child is not allowed to be born, how she is going to be educated. The female foeticide is committed on a large scale in the country. It is the biggest crime. 'Laadli Laxmi Yojana' launched in Madhya Pradesh is a very good scheme to check female foeticide. Unless female foeticide is stopped, the other three objectives cannot be fulfilled. So far as the women reservation is concerned, there is no commitment as such in the President's Address to get the Bill passed. However, it says that the Government

intends to take measures in this regard. The measures would be taken and the promise would just be fulfilled. The time frame has to be spelt by the Government as to when the Women Reservation Bill would be passed.

Para 42 touches and ends with the mention of cross border terrorism on Indo-Pak border. The most pertinent topic remains untouched. Today, Pak is building up and enhancing its nuclear capability. I am pained to say

what we achieved during Atalji's rule, has been lost under Indo-American nuclear pact. We have imposed self-restraint on any future nuclear explosion and in case if it is carried out, the pact become null and void. The Prime Minister has to reply what steps the Government are taking to deal with the nuclear capability being augmented by the Pak. In this very paragraph, there is a mention of Tamil Lankans. Could we afford to sit silent at the inhuman atrocities being committed against our Tamil brethren? We should send our delegates there to assess the situation and suggest what measures could be taken to mitigate their sufferings to the extent possible. Then, in the paragraph 45 there is a mention of Indian diaspora. On one hand, we term them as our undeclared ambassadors, on the other hand we come across the reports of their sufferings abroad. What pain me most is when a responsible minister of the Cabinet says on the TV Channel 'what could be done since our mission are under staffed'. The people are not

bothered about the mission being under or overstaffed. We want our people and children to be safe there. Lot of will power and determination is required to fulfill the commitments made in the Address. What message is going to be conveyed to the people of the country if the ministers make such statement showing helplessness? Hence, a delegation consisting of young Parliamentarians be sent to Australia so that our people there could feel that someone is there to take care of them and the Government is sensitive to their cause. It should not take long time and nor there is any difficulty in it. Our President has talked of the aspirations and the hope of our youth. Whenever, there has been a crisis, our youth have played their role very responsibly. I am happy to see a large number of young Parliamentarians having been elected to Lok Sabha. I congratulate them. I look forward to the aspirations of the people being fulfilled by them. However, the Government need to take steps to help them fulfill those expectations. I have word of caution for the Government that the youth cannot wait for long. The youth gets impatient if there is inordinate delay and that impatience has in it the message of resentment brewing in them. It is accepted that we cannot change the picture in 100 days, but we can chalk out a blue print for the same. The Government has to formulate such a blue print. The people have elected them to govern the country and we have been

assigned the role of the watchdog as Opposition. We would support the Government if it undertakes good measures. We would caution the Government if it committed lapses and delays. Likewise, we would also caution it if it does not deliver. We would oppose if they make mistakes and lapses. We would put to the test the promises and points made in the Address and see if they have been accomplished or not.■

Let's make a new beginning

If Government does, we'll certainly reciprocate

— Arun Jaitley

"Mr. Deputy Chairman, Sir, this is the first address by the Hon'ble President after the elections to the new Lok Sabha. Democracy, itself, Sir, is a great leveller, and, elections in a democracy themselves are a leveller except that they can occasionally produce harsh results, which involve winners and losers. But, democracy itself, when it produces winners and losers, confers upon the winner the great sense of responsibility.

Today morning, when I came to the House, I thought that when the speakers from the Treasury Benches initiate the motion, that burden of responsibility will confer a sense of modesty and humility. And I must express the deep sense of disappointment that I found it grossly lacking.

However, we, in the opposition, certainly do not intend to be provoked by this attitude of lack of modesty and humility which a winner must inherently have because we were told from beginning to the end, where most of us, in the opposition, have gone wrong and where our conduct and attitude was to be found lacking. Those who are defeated in an election also have a responsibility in a democracy and that responsibility is to conduct yourself with a certain amount of graciousness, have a certain amount of dignity, but, at least, have a sense of determination and fulfil the role which is conferred on you. And, Sir, that role which is conferred on us, I can assure you, is a role which we will discharge purely guided by national interest. There are going to be several areas where we are going to support and even endorse the position of the Government. That is what is expected from us. There are going to be several areas where we have to caution the Government, particularly when certain pitfalls are visible. And when we find the Government going astray, needless to mention, we are going to fiercely oppose the Government on those occasions. That's a responsibility which is conferred on us and I can assure you, this House and the country, through this House, that various sections of the opposition in their own way are going to discharge this responsibility which is also a responsibility which is conferred on us

in a democracy.

Sir, I have no hesitation in admitting after a lot has been said about the election results that for me and my party the election results were a disappointment. We accept that with humility at our command.

But, at the same time, we are conscious of the responsibility that these election results have conferred on us. Sir, we read some very clear messages emerging out of these election results and some of these messages that we can read very clearly are that the electorate of this country is conscious of the fact that we live in an era of coalitions and an era of coalitions can also occasionally bring disturbances and even roadblocks in the functioning of the Government. Perhaps one of the great motivating factors to the Indian voter was a great desire for political stability. And, therefore, the electorate, pursued by that desire, gave to the Congress Party over 200 seats. Let them, therefore, be very conscious of this fact that 206 seats in Parliament are not akin to 403 seats in Parliament that they got in 1984. And, therefore, the manner in which they have to conduct themselves must also be conditioned by this fact. The electorate did want political stability and, therefore, in the last five years, when we found the Government lacking on several fronts, it may not be een as an endorsement by the voter of India of areas where the Government was found to be wanting. There are several areas. We can have a discussion at an appropriate time over them. But, it was this desire for political stability and when this desire for political stability has given them a larger number of seats, the Indian voter is now not going to accept any alibi for non-performance. In the last five years, it could be blamed on the allies. Today, it's being sought to be blamed on us. But, once you have a figure which is closer to the half-way mark along with your allies, no alibi for failure is going to be accepted this time for which you have got the benefit of doubt in the last 5 years. At the same time, the Indian voters have shown an immense amount of maturity. But even when we were losing, in a large number of States where the non-Congress parties have performed well, those non-Congress parties, including my own party, our allies in several States, some others who have moved away from us, either got an overwhelmingly large number of seats in those States or in some States, at least, got an absolute number of seats, and therefore, this is a clear mandate as of the electorate as we understand it today. I also do understand that the mandate today is also a representative of an aspirational India; people want India to grow. But we are cautious of the fact that when they want India to grow, this growth is at two levels.

It is at a level where there is a segment of our population which has not been able to benefit from the benefits of that growth process, and therefore, when the President's Address very enthusiastically mentions

phrases of great achievements which have helped those sectors, the hard reality is that that sector is still under-privileged. There is also another segment which is an aspirational India where the aspirations are larger, and understandably so, and therefore, this mandate also reflects on the Government desire and the electorate desire to really perform as far as these areas are concerned.

Sir, I had said in the beginning as to what role we intend to play.

In any Westminster system, the conventional role of the Opposition is to oppose. But in evolving and maturing democracy, this role has also evolved, and therefore, as I said, our principal object when we will be guided by national interest is, how to strengthen the country. We have to strengthen this country in terms of making its borders secure, we have to strengthen this country in fighting terror within the country, we have to strengthen this country in our endeavour to help the Government so that it can vanish all forms of poverty and sufferings. We have to strengthen this country by even pursuing the goal of social justice. Now, these are several areas of strengthening the country. One of the principal desires of an aspirational India is to become a developed economy by 2020. Now, in each of these endeavours, there are areas where we will support the Government, there are areas where we will caution the Government, and there are certain areas where we will be required to fiercely oppose the Government, and when I read and when I heard the hon. President's Address, I was a little disappointed on one score. I did expect a mention, an emphatic mention, of the manner in which racial attacks are being carried out against persons of the Indian origin in Australia. Now, this is something which is very current and contemporary, and any sensitive Government which says with a sense of pride that we have million of Indians in our diaspora living abroad and living all over the world, would have been concerned with the plight of the Indian community which is being subjected to such inhuman and racial attacks. I think, it is an oversight as far as the draftsman of the Address is concerned that this one important area which is extremely current and of great sensitivity to every Indian is missing. But without emphasising that any further, I think we must all in this House as in the entire country resolve to stand behind the Government in its endeavour to pursue this case with the Australian authorities and to make sure that these kinds of inhuman and barbaric attacks on persons of the Indian origin are not repeated any time in future. Sir, when I said we will support the Government on issues, I can draw satisfaction from certain areas of the President's Address.

When I read the Address, I also read my party's manifesto and I have no hesitation in saying that there are several areas which are of common

national cause for the entire political community; our roads may be different, but the ultimate destination is really the same, and, therefore, the emphasis which the President's Address has given on achieving a high growth and a low inflation, I think, is something on which we will stand solidly behind the Government. The President's Address, in terms of the desire of the Government to legislate the Food Security Act so that the impoverished people in India living below the poverty line can have the benefit of 25 kilograms of foodgrains at affordable prices, is an inherent path of the Right to Food. And we do believe that this Right to Food, as a large number of liberal economists say, is a populist scheme; this free distribution of rice or cheaper distribution of rice or wheat is a burden on the Exchequer, but in the political community, since we are directly concerned with the plight of people who suffer, this is, in fact, far from populism. It is a Right of Food and the benefit of the Government resources, the Exchequer reaching the weakest man and, therefore, in States which have been implementing, particularly Chhattisgarh,—now, I am told, Orissa has also started it—it has worked every effectively. And if the Government brings this, really implements this Right to Food, I have not the least doubt in saying that we, in the Opposition, would strongly stand behind the Government in implementing this across the country. As for the determination which the Government has ostensibly expressed for having a zero tolerance as far terrorism is concerned, my party had occasionally felt, in the last five years, that the Government was soft on terror, and we were amongst people who were considered as those who really stand by this phrase 'zero tolerance on terror'.

Accusations were hurled at us. I am not going to say, for a moment, that it is my ideological victory or my party's ideological victory that you have been compelled to use the same language, after 26/11, which we have been using, but if the Government, really, effectively implements this zero tolerance towards terror, there is no reason why we will not stand behind the Government while this is done. Sir, the 'one rank-one pension' issue was raised by us in our manifesto. The Government had said that they would examine it by the end of June, 2009. I would seriously urge the Government to not merely examine it but also to concede to this long-standing demand of the Indian Armed Force. I think they secure our country and they deserve the benefit of not being treated in a discriminatory manner and, therefore, the 'one rank-one pension' demand of the Armed Forces should be conceded to at the earliest.

The Women's Reservation Bill has been pending for years and years together. In the last five years, we were disappointed because, repeatedly, we were being told that the Women's Reservation Bill would come, but even the introduction of it had to wait till the very end of the Government.

And, therefore, the seriousness of this Government in introducing the Women's Reservation Bill and seriously approving and supporting that Women's Reservation Bill was itself doubtful. The

Government has said that they intend to do so. If the Government does so, I am sure, as far as the BJP is concerned and as far as other segments of this House are concerned, we would strongly stand behind the Government in supporting that Bill in the next 100 years and.... Sorry, in 100 days. I am glad that Mr. Yechury who is also going to support us and the Government on this Bill corrects me. If this Bill is brought and passed within 100 days, I think, the credibility of Indian politics itself will go up because we have been promising the voters and the women of India that we will give this reservation, and for almost a decade this has been pending; it is about time that we did it in the next 100 days, Sir.

Sir, there is one issue of caution that I have, on which the President's Address does not state anything. During the earlier tenure of this Government, in the last five years, there was a lot of debate as far as the Indo-US nuclear deal was concerned. Some taunting remarks were made in that context even today. We had repeatedly said that we stand for a close cooperation between the United States and India. But the nuclear deal should not merely be the touchstone as far as determining that relationship is concerned.

There was a genuine apprehension that we had agreed to some areas where we felt we should not have agreed. I do not go into that history. But there are going to be three areas in the days, weeks and months to come where our own autonomy and independence is going to be at test. The three areas are those where our stand and that of the United States is significantly different. The signing of the NPT is one area; the agricultural negotiations in the WTO is the second area; and the capping of the carbon emission norms in the climate change negotiations which are going on is the third area. I am sure the Government which has followed a particular course of action, which has been the consistent national stand as far as India is concerned, is conscious as far as the interest of India's agriculture is concerned and India's industry is concerned. The agricultural negotiations have not proceeded significantly in the past five years. Now there is a considerable amount of pressure on us to yield. The Indian position in short has been that unless our agricultural farmer is really a sustenance farmer he cannot compete with the subsidised farming as far as the United States is concerned, the European Union is concerned and the other subsidising nations are concerned. We must bear in mind that as far as these areas are concerned nowhere in the world foreign policy and trade policy necessarily go together. Europe and United States are occasionally raised against each other as far as trade policy is

concerned; though they may have the best of political and diplomatic relations with each other. Because ours is a sustenance farmer, he cannot compete this huge amount of subsidies that the developed countries give, which must come down. The Government of India in the last five years has pursued this stand and pursued it vigorously. India is being blamed by the developed countries for not allowing the deal to go through. On the contrary, we are being told that you reduce your tariffs so that the subsidised agriculture can come and invade the Indian market. Even if it did not invade the Indian market, it will, at least, prevent our surplus from going into the global market, compelling our agricultural produce to be dumped in our own market and depress our prices. So those subsidies really are a death knell as far as the Indian farmer is concerned. Without any significant reduction in those subsidies, by just concealing them into the environmental category in the green box, today there is an effort to get us to fall in line and sign that deal. I wish to caution this Government that this is one area — the hon. Minister of Commerce, Shri Anand Sharma was here just now — where the Government would not yield and stand by what our conventional Indian position is. The climate change negotiations are currently on. There also, the effort is that the developed countries have already had and tasted the fruits of development. They have a huge amount of industrialised growth and therefore, their emissions or what pollutes the environment is far higher than us. Now the entire effort is to trade in that pollution and ask the developing or the weaker countries to buy it because our emissions are reasonably low; or, to cap it in such a manner that our further industrialisation itself can get capped at certain stage. If we agree to some of those proposals, it will be capping our growth itself. Therefore, while maintaining the best relationship between India and the United States, I think these are areas in which the Government of India will have to be cautious as to which course it really has to tread on in the course of coming months and years.

Sir, at certain places, when the President's Address talks of Government's achievements, I can quite understand that a new Government, enthusiastic with a positive mandate, may exaggerate its own past performance. At the same time, let us be very clear about where we stand as far as the state of the nation is concerned. We always refer to the GDP growth rates. I cannot see any significant policy, during 2004-09, which really related to improving upon the GDP growth. In 1991, we started a particular process. The policy decisions, between 1991 and 2004, accelerated the growth rate as far as India was concerned, because the growth is substantially entrepreneurial. There was a boom in the global market. The going was good, and we also looked good in the whole process. But the test of great administrator is not that when the going is

good that you are at your best. What happens when the good is not so good? And, in the last one-and-a-half years when the going was not so good, we virtually saw the Government which was paralysed as far as the economic decision-making was concerned. Therefore, the Government could have a legitimate alibi to say, "My allies didn't allow it. My friends didn't allow me to do so." But, today, it has lost all those alibis. Therefore, today, it has to really perform as far as its own performance is concerned. Five years saw a lot of indecision.

You arespeaking in terms of patting yourself on the back as far as employment figures are concerned. The 2004 manifesto promised 1 crore new jobs every year. Then, we should have had five crore jobs more as of today. We used to hear every year, words called 'Outcomes and Outlays'. This time that is missing. This expression 'Outcome and Outlays' is now replaced with Performance Reports. It is just another name; it is a synonym for Outcome and Outlays. Now, as far as the Outcomes and Outlays of 2004-05 are concerned, as against these f ive crores of jobs that you promised in the last five years, how many have you effectively added? The Commerce Secretary's statement two days ago stated that the export sector itself had lost 1.5 million jobs. The industries are closing down. It is a hard reality. The industrial growth has slumped.

Look at infrastructure. I was just going through the infrastructure figures of the last five years. Now, the figure states, relating to the Golden Quadilateral project, which were started and contracts awarded pre-2004, 98-99 per cent completed. Now, when you look at the progress of the North-South and East-West Corridors, you have a figure of 7300 to be constructed. But only 3541 have been constructed. In Phase III, out of the figure of 12,109, which were to be constructed, what have been constructed so far are 827. This means that less than 7 per cent of Phase III of the National Highways has been completed. And we pat ourselves on the back and say that infrastructure is doing very well. The murmurs, which we heard at the stage of the Cabinet formation, which is the Prime Minister's prerogative, that some people are to be kept out because they found that they were the road blocks as far as infrastructure is concerned. The Left never told you, "Don't create any infrastructure." Your own friends were given the responsibility. Now, when we look at the Railways, we were told that the Railways was a very populist area in the last five years. In 2008-09, that is, the year which is just over, to attract 1 crore of private investment, an investment of Rs.25 crores has been tied up. What has been received is not a single rupee. Twenty-six stations have been identified for making them world-class stations. They said, "The railway stations will look like airports." Not a single railway station has changed nor has any improvement been seen. Even the tendering stage has not

started.

Now, shipping. It was told that new berths for major ports would be created because the trade load is through the berths. So, they planned to create 52 berths between 2006 and 2012.

Three-and-a-half years of that six years' period is over. So far, contracts have been awarded only for six berths. This is how infrastructure is moving. Then, we come to rural roads. The plight, as far as rural roads is concerned, itself is a matter of great concern. As regards the agricultural sector, I saw a phrase, a phrase borrowed from the American political phraseology, where the hon. President says, 'my Government gave a new deal to agriculture.' President Roosevelt gave a new deal in some other concepts. So, this is a 'new deal' to agriculture where a record number of farmers have committed suicide in five years. We pat ourselves on the back that the Indian agriculture has become a utopian situation. They talk about irrigation, remunerative price for the farmer, rural infrastructure, drinking water, electrification, etc., and now we are told that all these promises will come. But I am wondering how these promises would be implemented. You have to be a decisive Government in order to generate economic activity so that governmental revenues could go up. If the Government has more money in its pocket, it can certainly give free ration to the poor, and implement all the social schemes. But, you are an indecisive Government. So, how are all these promises going to be fulfilled at a stage when you have a record highest fiscal deficit as far as India is concerned? In the Interim Budget, the Finance Minister said, it is six per cent. Now, six per cent was considered a figure which had been deliberately depressed. Once the actual figures come out, the figure will be known. All economists tell us you add the off-balance sheet items to that six per cent or the extended figure of six per cent. You add the fiscal deficit of the States. Not one man is going to accept that it is going to be anywhere below double figures. It is going to be well into double figures, much more than twelve per cent. And with a twelve per cent odd fiscal deficit, there are only two ways you can finance it. You become a high-tax Government, and if you become a high-tax Government, it has an adverse affect on growth again. Or, you generate economic activity by being a more decisive Government. Now, I think, this is an option which the present Government has and it has to decide which option it is really to follow as far as its economic roadmap is concerned.

Talking of the situation in our neighbourhood, I was very curious why the Foreign Policy chapter, as far as this speech is concerned, was somewhat inadequate. It was quite extended in the February Address of the President. In the February Address of the Government, the Government was patting itself on the back saying that as far as Pakistan is concerned,

our diplomatic initiatives have brought Pakistan on track; Pakistan has now fallen in line; it is cooperating. There is a lurking doubt in India whether the trial of the person who masterminded the attacks on Mumbai in 26/11 is, by any internationally-accepted standards, a fair trial or a collusive trial. There are doubts and suspicions being expressed globally. The Pakistani Prime Minister has now responded by saying, 'Kashmir is the root cause.' So, whenever Pakistan wants a hostile attitude to be developed, Kashmir again emerges, and that is again a reiterated stand that the Pakistan has taken. How do we see our borders? Our borders can never be secure if the spill-over of what is happening immediately outside our borders gets carried into India. So you have Taliban which is creating turmoil in Pakistan; you have the Maoists creating instability in Nepal; you have the LTTE problem, which we all hope, gets resolved as far as Sri Lanka is concerned. You also have the Huji which has, besides illegal migrations from Bangladesh into India, that the Supreme Court referred to as an invasion of India, has now made Bangladesh into a base for engineering all domestic attacks which take place, as far as India is concerned.

So, we are a country which is now surrounded on all sides..... So, you now have a situation where on all four sides we have the Taliban, the Maoists, the LTTE, the HuJi, and we have Pakistan which is not falling in line! I think, the Government must now stop this; electoral victories are sufficient to prove a point.You must now really think in terms of tackling this situation.

Sir, the 26/11 trial is perhaps the most important of the terrorism trials which have taken place in India. We are told by the hon. Home Minister at some stage, and it is an argument which I heard for the first time, that the general IQ of the Members of his party is higher than that of my party! I have never seen political debates falling to this level. Suddenly I realised how all the gentlemen with a superior IQ were masterminding this Government as far as the Mumbai trial is concerned. The first thing we did was appoint an ineligible person as the prosecutor so that the global community watching the trial will say that the whole trial is vitiated. The second thing we did was to send an incorrect DNA of Kasab to Pakistan and then suddenly say that it was a clerical error.

The third thing we did was—and I do not know what happened to the lady thereafter—we were told, 'we now discovered Qasab's mother who is coming to meet him and that we are a very liberal society, we are allowing her to meet him', and then we did not hear of her at all. Sir, such sensitive trials are not conducted in a shabby manner. I think, those who boast of a very clever IQ, their performance must reflect this adequately.

Yesterday, Sir, two important events have taken place. The Hyderabad

police has said that three terrorists have again entered India with the idea of creating terror. But the second, more important, event has taken place. The U.S. has clubbed us with Pakistan and issued a travel advisory that visitors must not visit India because India is no longer a safe place to visit! It is the first time that this has happened. I can imagine this happening if this country were in chaos. The Home Minister rightly said, 'We reject this and we will call upon the U.S. to withdraw this advisory, India is perfectly a safe destination.' We all join him in that request. But why has a panic of this kind been created? The panic of this kind gets created when the Government assumes a certain amount of arrogance to itself and the Government starts believing that it is the sole repository of all wisdom.

So, when a cricket tournament was to be held in India and State after State said that we will hold it and no worry, what is the difficulty? India is such a large country, holding one cricket match every evening in one part of the country is not a national problem, but it was the Government of India which created panic. And, the Government of India said, 'We would not allow this to happen.' So, the domestic cricket tournament went to South Africa. That day, we had cautioned the Government, 'Please understand the consequences of this. The consequences of this are going to be that you are going to be clubbed with Pakistan. People will stop investing here because India is not a safe destination, tourists will stop coming here, travel advisories will not come. What will happen to the Commonwealth Games?' So, when the Government of India created panic, the Australian Davis Cup team said, 'India is not a safe destination, we would rather lose and concede, but we would not play in India.'

The United States has now turned around and issued a travel advisory against us. I think, this Government needs to realise that it seriously believes, which we all do, that India is a safe destination. The Government of India must seriously stop treating each one of these issues as purely partisan. A large number of India's polity and governance is non-partisan, and, therefore, we can in national interest rise to the occasion and not create a panic of this kind merely because some demand is being made somewhere and we must being on the other side of the political fence necessarily oppose it. Sir, the Government has given a large number of programmes and schemes in the President's Address. But normally a President's Address is much more than a catalogue of governmental schemes, particularly after election in the first five years, it has to be a vision statement of next five years. The vision is lacking in this document but it is a catalogue as far as Government schemes are concerned. The Government implements these schemes, some of these schemes we will fully endorse and I wish it the very best. We in the Opposition will certainly cooperate with the large number of these schemes, many of them

are in national interest, but we would also like to set a particular yardstick by which we will measure this Government. I said, we are not going to oppose merely for the sake of opposition, we are going to be supportive of several areas. We can caution them of several areas. What are the steps this Government is going to take to make our borders secure in order to manage the situation, which is taking place around our borders, and improve upon the domestic security as far as India is concerned? How will the Government rise above this propaganda figure that we kept inflation under control? Inflation came under control not because of the steps of this Government but inflation came under control because you had a global recession and therefore, the slowdown impact was felt in India. But we are in a strange situation and the hon. speaker from the Treasury Benches said that our economy is different from world economy. Yes, it is because even in a recessionary trend foodgrains prices have continued to rise and therefore, there is a significant amount of foodgrain-inflation, which affects this entire 'right to food' that we are talking about. Therefore, what steps will the Government take as far as this is concerned? How will the Government expedite the infrastructure creation? You are an alibi saying that the choice of the Ministers last time was under compulsion, we changed them; we brought better people. Well, we are very happy, we compliment you for doing that but please tell us what are you going to do as far as infrastructure creation is concerned? What are you going to do beyond patting your back to improve the lot of agrarian India in terms of rural infrastructure, in terms of procurement prices as far as farmers are concerned, to get them to rise as far agrarian poverty is concerned? You have a very tall promise that you are making India slum-free by 2014. Sir, the present set of Indian politics will get the greatest credit, the Government will get the credit if it does that. We will support the Government in every measure to do that. But then there must be an expectation management, which any person with some level of understanding of politics must have and, therefore, the Government has laid down a very important test for itself that in 2014 India will be a slum-free India. If people see slums it will be synonymous for the Government failure. Therefore, the Government is going to be judged by the standards that it has now laid down for itself. The issue of unemployment, which I had raised, both rural and urban employment, and to foot the bills of all these schemes, which are contained in the speech. Is it going to be a very high-tax Government?

Is it going to start a decisive decision-making process? How will it handle the multilateral dialogues in the climate change negotiations, in the WTO in the months to come? Two important areas, Sir, which need to be mentioned.... One is with regard to the misuse of several institutions like the CBI which took place in the last five years.

Every time an ally supported you, the case against the leader of that ally was downplayed by the CBI. The moment you had certain acrimony with that ally, the CBI expedited as far as case on him or her is concerned. We need structural, including legislative, reforms to maintain the independence of institutions like the CBI, because, in the last five years, the credibility and the autonomy of that institution has completely destroyed. It has not been diluted; it has been destroyed. Some of the most eminent thinkers in this line have publicly expressed their views as far as this subject is concerned.

Sir, now, I come to the issue of Sri Lankan Tamils. The rehabilitation of Sri Lankan Tamils is something on which the Government of India has to play a pro-active role. I come to education sector. Sir, I read statements of the new Minister of HRD who has been promising a lot on this front, both in terms of elimination of illiteracy, primary education, quality global education at affordable prices, etc.

Therefore, these are all the areas. When the Government lays down a road map for various Governmental schemes, these are all areas where we, in the opposition, laying an important yardstick and judge the Government by its performance in each one of these areas.

Sir, I have a few suggestions to make for the Government before I conclude. The hon. Chief Minister of Bihar has repeatedly said that Bihar needs a special package. In fact, a lot of backward areas need it. Sir, Bihar, particularly, after the division of the State, needs it a lot more. This is one area which needs to be seriously considered by the Government. Sir, the hon. President's Address mentions a desire of the Government to bring a law which has been hanging for the last four or five years to check communal violence. The right things or even the good things that the Government wants to do have to be done in a right manner. Shivrajji is here. I think, he has conceived this Bill. It went to the Standing Committee and ultimately it was found and there was an overwhelming opinion that law and order is a State Subject, can the Centre legislate on this and if the Centre legislate, the code eventually become some kind of an encroachment as far as the federal structure is concerned. It is because it would directly enter into the law and order areas. Now, this is one area the Government has to keep in mind, particularly when the Government goes ahead as far as this proposal is concerned.

I am glad, Sir, that the word 'D' is back. The word 'D' in Indian politics means 'disinvestment.'

Sir, I am glad that the former Home Minister effectively endorses what I have said. There is a provision in the Constitution that the Centre can take consent from two State Legislatures, pass a Bill and it will apply

only in those States which then keep approving that Bill, because it is a subject which comes under the purview of State List. So, you have promised something in the President's Address to deal with the area which squarely covers as far as the State List is concerned and the Parliament does not have legislative competence to deal with that area.

Sir, as I said, the 'D' word of Indian politics means 'disinvestment.' When I heard Shri Satyabrat Chaturvedi advocating the cause of disinvestment, I thought that was hearing Mr. Arun Shourie. This was borrowed wisdom. I am glad that it has travelled to the other side. But, it need not be regulated merely by a policy regulation which was applied to each one of the PSU across the board. Please examine the case of each PSU where do you require 51 per cent and where you don't require 51 per cent. The whole intention must be to keep efficient performance of those companies which are valuable assets and also see that the resources can be used.

Finally, Sir, something has been said in the President's Address about the Sethu Samudram Project. I would only urge the Government to seriously examine before mindlessly saying that we will go ahead as is where is, because we have the mandate.

What is the cost-benefit assessment as far as this project is concerned? What is the amount of investment that you are going to make and what are the kind of returns required in coastal shipping? There have been several people who have conducted economic studies, and they have different views on this subject. If you are so keen to go ahead, rather than polarising the society — as Mr. Keshava Rao said, I am sure the Government will follow his advice not to polarise the society — seriously examine the alternative routes. When you take steps of this kind, you obviously find some kind of social discontent taking place. And, I am sure, the Government will seriously consider that it need not start on the wrong foot once again once it has got a mandate to rule the country.

I wish the Government the very best. I am sure the Government started in the President's Address with some intentions for the future; but, at least, in this House it started with a sense of acrimony. I am sure the Government will overlook what its representatives have done today and, at least, carry on with the spirit that the Prime Minister said to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, "Let's make a new beginning". If the Government does, we will certainly reciprocate.

Thank you, Sir.

सारांश

हम राष्ट्रीय हित के अनुसार ही अपनी भूमिका निभाएंगे। हम कुछ क्षेत्रों में सरकार के रूख का समर्थन करेंगे। हमें विशेष रूप से जब भी कुछ खामियां नजर आएंगी, सरकार को सतर्क करना होगा।

मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि चुनावों के परिणाम हमारे लिए एक निराशा थे। हम उस जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं जो कि चुनाव परिणामों ने हमें सौंपी है। भारतीय मतदाता के प्रेरक कारणों में से एक कारण था राजनैतिक स्थायित्व की बड़ी आशा और जब इस राजनैतिक स्थायित्व की आशा ने उन्हें बड़ी संख्या में सीटें दी हैं तो भारतीय मतदाता गैर निष्पादन की स्थिति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा।

उसी समय भारतीय मतदाताओं ने काफी परिपक्वता दिखायी है। मैं इस बात को भी समझाता हूं कि आज जो हमें जनादेश प्राप्त हुआ है वह महत्वकांक्षी भारत की आशा को दर्शाता है, लोग चाहते हैं कि भारत विकास के पथ पर आगे बढ़े। हमारा मुख्य उद्देश्य यह होगा कि राष्ट्रीय हित के अनुसार देश को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। हमें देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाकर देश का सुदृढ़ीकरण करना होगा। हमारा प्रयास होगा कि सरकार की मदद की जाए ताकि यह सभी प्रकार की गरीबी और कष्टों को दूर कर सके। महत्वकांक्षी भारत की मुख्य इच्छाओं में से एक है सन् 2020 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना होगा।

मैंने अपनी पार्टी के एक घोषणा पत्र को भी पढ़ा और मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि समूचे राजनैतिक समुदाय के लिए आम राष्ट्रीय हित के हैं, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं परन्तु अंतिम गन्तव्य एक ही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऊंची विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति पर जोर दिया गया है, मैं समझाता हूं कि ये एक ऐसा मामला है जिसका हम सभी समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाने का उल्लेख करता है। मुझे यह कहने में जरा भी संदेह नहीं है कि हम विपक्ष में सरकार को इसे पूरे देश में कार्यान्वित करने के लिए सरकार का समर्थन करेंगे। हम आतंकवाद को पूर्णरूप से समाप्त करने का वास्तव में समर्थन करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में 'एक रैंक एक पेंशन' मुद्दे को उठाया गया है। सरकार ने कहा था कि वह जून 2009 के अंत तक इसकी जांच करेगी। मैं सरकार से गंभीरता से यह निवेदन करूंगा कि वह न केवल इसकी जांच करे बल्कि भारतीय सशस्त्र सेना की लंबे समय से चली आ रही मांग को

पूरा करे। महिला आरक्षण विधेयक कई वर्षों से लंबित पड़ा है। यहां तक कि इसके पुरःस्थापन करने के लिए सरकार को अंत तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम विधेयक के समर्थन के लिए सरकार का पूर्णरूप से समर्थन करेंगे। पिछले पांच वर्षों में भारत अमरीकी परमाणु करार के बारे में काफी चर्चा की गई थी। हमने बार–बार यह कहा था कि हम अमरीका और भारत के बीच निकट रूप से सहयोग के पक्षधर हैं।

परन्तु परमाणु करार को संबंधों को निश्चित करने के लिए एकमात्र कसौटी नहीं माना जाना चाहिए। यह एक वास्तविक आशंका थी कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में सहमति दे दी थी जिन पर हमें सहमति नही देनी चाहिए थी। हम हमेशा सकल घरेलू उत्पाद विकास दरों का उल्लेख करते हैं।

मैं 2004–09 के दौरान किसी ऐसी महत्वपूर्ण नीति को नहीं देख पाता हूं जो कि वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद के विकास से संबंधित थी। हम प्रतिवर्ष 'परिणाम और परिव्यय' शब्द सुना करते थे। इस समय यह शब्द गायब हैं। अब 'परिणाम और परिव्यय' शब्दों के स्थान पर निष्पादन प्रतिवेदन आ गए हैं। वाणिज्य सचिव के दो दिन पहले वढ़तव्य ने यह दर्शाया था कि निर्यात क्षेत्र ने 1.5 मिलियन नौकरियों को खो दिया है। उद्योग बंद हो रहे हैं। ग्रामीण सड़कों की दुर्दशा अत्यंत चिंता का विषय है। माननीय राष्ट्रपति कहती हैं कि मेरी सरकार ने .षि को नया रूप दिया। .षि का यह नया रूप है जिसमें पिछले पांच वर्षों में किसानों की रिकार्ड संख्या में आत्महत्याएं हुई। वे सिंचाई, किसान को लाभकारी मूल्य, ग्रामीण अवसंरचना, पेयजल, विद्युतीकरण का उल्लेख करते हैं। ये सभी वायदे उस चरण पर पूरे किए जा रहे हैं जबकि भारत में उच्चतम वित्तीय घाटा चल रहा है। आप उच्च कर की सरकार बन जाते हैं और यदि आप उच्च कर सरकार बन जाते हैं तो इसका विकास पर पुनः प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति का अभिभाषण विदेश नीति के संबंध में अपर्याप्त था।

राष्ट्रपति के फरवरी के अभिभाषण में यह काफी विस्तारपूर्ण था। सरकार स्वयं को यह कहकर शाबाशी दे रही थी कि पाकिस्तान के संबंध में कूटनीतिक पहलों में पाकिस्तान सही पटरी पर आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहकर उत्तर दिया है 'कश्मीर मूल कारण है' अतः जब भी पाकिस्तान वैमनस्य पूर्ण रवैये को बढ़ाना चाहता है कश्मीर मुद्दा उभर कर सामने आ जाता है। हमारी सीमाएं कभी भी तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक कि देश की सीमाओं से बाहर होने वाली घटनाओं का असर हम पर पड़ता रहेगा।

हमारी ऐसी स्थिति है जहां हमारे चारों तरफ तालिबान, माओवादी, लिट्टे और हूजी है। सरकार को इसे रोकना चाहिए। 26/11 का मुकदमा आतंकवादी मुकदमों में से महत्वपूर्ण मुकदमा है जो भारत में हुआ। पहली बात जो हमने की, वह अयोग्य अभियोजक की नियुक्ति करनी थी। दूसरी बात कसाब का गलत डी.एन.ए. पाकिस्तान को भेजना था और फिर तत्काल कहना कि यह एक क्लेरीकल भूल थी और तीसरी बात कसाब की मां को उससे मिलने देने की अनुमति देना था। इस तरह के संवेदनशील मुकदमों को गलत तरीके से शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि तीन आतंकवादी आतंकवाद फैलाने के विचार से घुस चुके हैं। परन्तु दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अमरिका ने हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है और एक सलाह दी है कि आंगतुकों को भारत में यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यात्रा के लिए भारत अब सुरक्षित स्थान नहीं रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है। गृह मंत्री जी ने ठीक कहा, हम इसको अस्वीकार करते हैं और हम अमरिका को इस सलाह को वापस लेने के लिए कहेंगे, भारत पूरी तरह से एक सुरक्षित स्थान है। हम सब उनके इस अनुरोध में शामिल हैं। भारत इतना बड़ा देश है कि देश के एक हिस्से में हर शाम को एक क्रिकेट मैच कराना कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं है परन्तु भारत सरकार ने यह डर पैदा किया है। इसलिए घरेलू क्रिकेट मैच दक्षिण अफ्रीका में हुए। लोग यहां पर निवेश करना बंद कर देंगे क्योंकि भारत एक सुरक्षित स्थान नहीं है, पर्यटक यहां आना बंद कर देंगे।

भारत एक सुरक्षित स्थान है। भारत सरकार को इन प्रत्येक मुद्दों को गंभीरता

से रोकना चाहिए। सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में काफी कार्यक्रम और योजनाएं दी है। इस दस्तावेज में दूरदर्शिता का अभाव है क्योंकि जहां तक सरकारी योजनाओं का संबंध है, यह एक सूची होती है। सरकार इन योजनाओं को क्रियान्वित करती है और कुछेक योजनाओं के लिए हम इस सरकार के साथ पूरी तरह से हैं। सरकार को हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने और भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुद्रा स्फीति इस सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के कारण नियंत्रण में नहीं आई परन्तु यह भौगोलिक मंदी के कारण आई और इसीलिए भारत में मंदी का असर महसूस किया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से भिन्न है। मंदी के दौर में भी खाद्यानों की कीमतें बढ़ रही हैं और जिस खाद्य के अधिकार की बात हम करते हैं, वह इससे प्रभावित हुआ है। एक वायदा किया गया है कि भारत 2014 तक स्लमफ्री हो जायेगा। इस पर हर कदम उठाने के लिए हम सरकार का समर्थन करेंगे। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनकी चर्चा किया जाना आवश्यक है। एक मुद्दा सी.बी.आई. जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के दुरूपयोग के संबंध में है, जोकि पिछले पांच वर्षों से हो रहा है। हमें सी.बी.आई. जैसी संस्थाओं की स्वतन्त्रता को बरकरार रखने के लिए वैधानिक सहित ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है क्योंकि पिछले पांच वर्षों में इस संस्था की विश्वसनीयता और स्वायत्तता पूरी तरह से खत्म हो गई है। श्री लंका के तमिलों के पुनर्वास पर भारत सरकार को एक सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। नए मानव संसाधन मंत्री ने निरक्षरता उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा आदि के बारे में काफी वायदे किये है।

बिहार के माननीय मुख्य मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि बिहार को एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। वास्तव में काफी पिछड़े क्षेत्रों को इसकी आवश्यकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। सरकार को राज्यों और केन्द्र के विषयों के बारे में ध्यान रखना होगा। जहां आप 51 प्रतिशत हासिल करते हैं और जहां आप 51 प्रतिशत हासिल नहीं करते हैं, इन मामलों के कृपया प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की जांच कीजिए। पूरा ध्यान जिन कंपनियों के पास कीमती धरोहर है, उनके प्रभावी निष्पादन को बनाए रखना है और यह भी देखना है कि उनके संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में कुछ कहा गया है। काफी लोगों ने आर्थिक अध्ययन किया है और इस परियोजना पर उनके अलग–अलग विचार हैं। सरकार को वैकल्पिक मार्गों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।■

Present Situation of the country
is much more complex and treacherous

— Arun Shourie

Mr. Chairman, Sir, I would like to have this opportunity to follow Mrs. Jayanthi Natarajan on the President's Address, and, I will be taking advantage of the presence of Mr. Antony to really begin with the paragraphs 41 to 44 which deal with foreign policy, which is an area of your pecialisation and interest, and, paragraph 12 which deals with defence, and, then, come to the economy, and, finally to what I regard as most important thing that needs to be resurrected and which came to be neglected in the last few years. I shall be pointing out, Sir, that the situation is far more complex; in many ways, the situation is treacherous much more so than is evident from the President's Address, maybe the customary homilies are there only for that reason, but the situation is much more complex and treacherous, and, therefore, it would require much more greater effort on behalf of the Government and it will require all of us to join hands on constructive matter which come before the country in this regard.

Sir, of course, I would have liked the result to be other way round but I am greatly reassured that of the available alternatives, the result that has come about from the elections is the best possible from the available alternatives because I was mortified of the hurtling of the country towards not just the splintering of the electorate, not just coalitions but coalitions with weaker and weaker course, and, therefore, less and less effective governments, and, that has been stemmed for the time being, and, secondly, Sir, the senior Members of the Government of this new Cabinet are ones whom we can trust would not ignite that kind of adversarial reaction as happened in the last few years. For that reason, I would really follow what Mrs. Jayanthi Natarajan has said just now about the spirit in which we must approach these problems.

Sir, the lesson for all of us is the same that inside this House, we should really make it a competition for better ideas, not just for

thumping the tables about problems but for coming up with solutions and a competition for solutions worked out in detail, and, outside this House, wherever, whoever is in office, to provide exemplary governance.

Sir, the reason why I mention this is that it is true that our country has limitless potential and we have only had a glimpse of that in the last ten years. But it is equally true that there are several countries which had the spurts of growth of eight to ten per cent at a time, for fifteen twenty years at a time, but ultimately, fell into what is well-documented

phenomenon amongst economists, called the 'middle-income trap'. If you look at Philippines, Thailand, Brazil, or, Mexico, they all had very high growth, and, then they just coasted along precisely because of disarray in the field of governance, politics and public life. It is for that reason, and, in that spirit, Sir, that I shall take up these problems because I also feel that there has been, in India, a consensus in practice; whoever has been in office, wherever and whenever he has been in office has tried to do the same things, and, has been obstructed by those who happen to be in Opposition at that time. I have had this experience of five years when I tried to continue the policies initiated by Dr. Manmohan Singh and others and the same sort of things repeated later on. So, I do hope that this election will mark a new beginning - there are persons for whom many of us have had greater affectionate regards like Mr. Antony, Mr. S.M. Krishna and others -- and that we would all join hands in the types of things that need to be done. For instance, just now, apart from her observations on POTA, Mrs. Jayanthi Natarajan read out a list in fighting terrorism is a list on which in many of the matters, Madam, I can assure you that you will find the same thing in statements, representations and recommendations of all of

us. The Unified Identity Cards and so on, all of these things are matters on which there is a consensus in practice, and, we must translate that into a consensus in fact, in execution.

So, Sir, I will first take up paragraph 41-44 which deal with foreign policy, and, as Mr. Antony is here, I will then take up paragraph 12 which deals with defence, and, then, come to the economy. Sir, in these paragraph, as you will notice, all the familiar phrases are there like 'we want peace', 'we are for a peaceable world', 'we want close relations with the United Nations', 'we want close relations with China', 'we want close relations with Russia', 'we want Pakistan to be unified and prosperous' and all these

things.

But, Sir, the situation is much more complex. When, under your chairmanship, we discussed the attacks in Mumbai and its aftermaths, I had urged several things, the Prime Minister was here at that time, but I recall only two of them and you will see the consequences of disregarding those simple things. One of my points had been, "Please don't get into this business of sending evidence to Pakistan because you will actually then be putting Pakistan in the position of a judge". They will say, "No, this is not right. This is wrong". But, exactly the same thing happened. I had mentioned it as my first point and my suggestion was, "Don't run to 'mummy', that is, to the United States so as to deal with Pakistan". But exactly the same thing happened and the result is that in regard to Pakistan, we are exactly where we were after the Mumbai attacks. Second, we have become, in my view, precariously even dangerously dependent on the United States for dealing with Pakistan and for dealing with the threat from China. We have to remember two points about the United States with whom we want close friendship, and the paragraph is very eloquent on this. One is, it is today dependent on Pakistan, not the other way around. Second, it is dependent on China, not the other way around. It is dependent on Pakistan because of the fact that they want to continue somehow the fight which they have begun in the region till a time when they can make an honourable exit. Second point is that for financing the bail out packages, which are imperative for saving the United States' financial and economic system, they are today dependent on China continuing to buy United States treasury bonds. China already has the largest holding. And, thrice in the last six months they have shaken the tree of the dollar. The United States is each time reminded of that But we Think उस टेलीफोन एक्सचेंज से हम कुछ करवा सकते हैं। Sir, I mention this because I apprehend that there will be three new developments in the coming months and certainly in the coming year, to one of which Arun had drawn attention. But there are three developments that are going to cause great problems, and I would urge the Government to be candid with the House to take the people of India into confidence in regard to each of these so that the acrimonies that we saw in the last five years do not occur now. The first is that the next steps, the steps which were there implicitly and explicitly in the statements of our interlocutors from America that next steps in the nuclear deal will now begin to unfold. The first of these is, Arun mentioned this and as you know, Sir, with your vast experience in these

matters, that 2010 is the year for the review of the Non Proliferation Treaty. And there will be enormous pressure on India to sign this, not just to sign this but to sign this without being recognized as a nuclear weapon state. Please don't make hairsplitting arguments on this. It has serious operational consequences. Second point will be, there will be pressure on India to sign the CTBT along with the five-six of the countries so that it comes into force even though the United States Senate has rejected the CTBT. And, the pressure will be that we must sign it without what we have been insisting on, an internationally verifiable mechanism. Third, there will be pressure, it has already begun in their statements, for signing the Fissile Material Control Treaty. Again, we must sign it with what is now being termed as a 'nationally-verifiable mechanism' and not an internationally-verifiable mechanism. Our drafts, as you know, and our speeches in Geneva at the Conference on Disarmament always were, "No we will not sign it till there is an internationally-erifiable mechanism". I will tell you why. The United States and one other country have the capacity to verify whether fissile material production has been capped or not. So, what will happen is, as they shut their eyes to the proliferation activities of A.Q. Khan for years and years, they will say, no, they have stopped it but India has not stopped. So, we said, no, it must be an international mechanism for verification. In the draft, which the United States placed in Geneva in May, this phrase was inserted. And while in the first round, the statements of the Indian representative were an unambiguous reiteration of our position, within two days; there was an ambiguous statement. Fourth, we will be asked to sign the PSI on which the Prime Minister himself, as you remember, had said that in its present form it is discriminatory and we have reservations. Finally, Sir, there is a proposal for a much tougher additional protocol of the IAEA, much harsher than was under consideration last year. So, this is the first point of pressure as all of these things bear on defence. I am sure, Mr. Antony and a very seasoned man like Mr. S.M. Krishna would be alert to the consequences of our being dragooned into signing all these things.

Sir, the second point, which will come as a point of pressure, will be pressure of resuming the so-called 'peace process' with Pakistan and the essence of which will be concessions to Pakistan. I mention this, Sir, because it is only because of one member of the previous Government that the concession, which we had almost got to be made in 2006, was stopped. It was for withdrawal of our troops from Siachen down from the heights and to convert it into

an International Peace Park. It was stopped at the last minute and I wrote about it and expressed gratitude to that particular person at that time. Now the US has concluded that it is stuck in Afghanistan. Pakistan is central to its efforts. Within Pakistan, the Army and the ISI are essential. Therefore, the US and other allies must provide to Pakistan what it wants. Therefore, if they want F-16s, if they want arms, which will clearly be used, not against terrorist, but India, well, you have to satisfy them on that. But the Pakistan Army and the ISI will not be satisfied just with arms. They will require concessions being made by India which they can hold up within Pakistan. So, this pressure will certainly mount. And the only reason we have had some respite in J&K is, of course, the valour of our forces. But it is really also because Pakistan has been busy with its own problems. In the end, you know that they are fighting the terrorists in the NWFP and in Swat. But they are not doing anything to the terrorist infrastructure based in Punjab and in Pakistan-occupied Kashmir. In the end, the only way for them to deal with the monster, which they have created, would be to deflect that energy into India, and we have to guard against that. Sir, our going on appealing to the US अरे भई, देखो, उनको कुछ कहो, is not going to work. I will draw your attention to two things. Sir, just recall the sequence that has taken place in the last two weeks. The New York Times published a report based on American intelligence sources that Pakistan is rapidly escalating its nuclear weapons production programme. This was around 12th of May. On 14th May, the US Secretary of Defence, Robert Gates, and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Mullen, were testifying before the US Senate Committee on Armed Services. Just see what happened. The Senator in question, Senator Webb, says that he has seen written reports by credible commentators -- he was referring to this report -- that Pakistan is actually adding on to the nuclear weapons systems and warheads. And he asked, "Do you have any evidence of that?" Admiral Mullen said one unambiguous word which rang in the whole hearing. He said, 'yes.' So, four days later, at the State Department, the spokesman was asked why they are going on giving the seventeen billion dollars to Pakistan in aid. They are expanding the nuclear weapons programme. After that, the Senator actually has said something and that strikes me as something that we should be approaching with enormous concern.

We are talking all the time about the potential that Iran might have in nuclear weapons capability and the consequences of that.

Here is a regime which is much less stable. They are acquiring this. Why are you not linking these two? Five times, the State Department was asked about that and they said, "No, no. We are not going to link." So, you will see that they are not going to do our work and look after our interests in this regard. Nobody is going to do it. Sir, the third point that bears on defence and on foreign policy is that there will be much greater pressure even on management of our own security. You remember, Sir, the outrage in India after the attacks in Mumbai. You remember the consternation in India as to why the Government of India was not doing something in return. All sorts of wild things were said. I have said that wild things should not be done. It's only one thing that could be done. And, one answer or one fact of the matter or one explanation was that actually India has not built up a singular capacity that can work in such circumstances and that is to do a Kashmir to Pakistan in Pakistan. That is one answer and the other answer to which I want to draw your attention to is, there is an answer that is given by the American Secretary of State, Mrs. Hillary Clinton. In another hearing on April 23 before the House Appropriation Sub- Committee on State, Foreign Affairs and Related Programmes -- Mr. Antony will see this -- while they were talking about the attacks in Mumbai, listen to what she said. It is the future. She says, "We worked very hard as did the prior administration to prevent India from reacting." And she says, "But, these people will continue these attacks. Therefore, we do have a lot of work to do with the Indian Government to make sure that they continue to exercise the kind of restraint that they showed after Mumbai." She went further and said, "There have been a number high level discussions." The Prime Minister has come. Mr. Prime Minister, Sir, I was just talking about the testimony given by Hillary Clinton, Secretary of State in the House Appropriations Committee about the aftermath in Mumbai and she said, "We worked very hard as did the prior administration to prevent India from reacting." And she said, "Actually these types of attacks will continue. So, we do have a lot of work to do with the Indian Government to make sure that they continue to exercise the kind of restraint they showed after Mumbai." She went further. The Prime Minister is here; maybe, she was wrong; he will tell us. She said, "There have been number of high level discussions including between the US President and the Indian Prime Minister on the sidelines of the G-20 Summit in London. To do what? The quotation is "Raising the issue of how India can do more to clamp tamp down

any reaction on any front like Mumbai could have provoked." Now, therefore, Sir, we must bear in mind that this is the kind of pressure that will come. Every country will act in its own interest. It will act in its own interest as perceived by a handful. It will act in its own interest as perceived by a handful at that moment. Today, Saddam Hussein is very good as a counter to Iran and he must be financed, patronised and encouraged. Tomorrow, he is the devil. Today, the Taliban are very good. They must be created; they must be organised; they must be fired up; they must be armed to throw out the Soviets. Tomorrow, they are the devil. Therefore, Sir, my first point is for Mr. Antony. My dear friend, Tarlochan Singh is here. After Mumbai, he quoted Guru Nanak. Exactly that is what we need. We need to do much more to build up what the Chinese call 'our comprehensive national strength'.

He said Please look not at the endearing statements of one ruler of Pakistan, I am transient fellow or not. (H) and all those activities continue. Look at the nature of Pakistani State and society. Has that changed? Third, I will come to this about China, its aim, the capacity it is acquiring and what it is doing actually on the ground to which I will just turn. Don't recreate and make a world of make-believe, a sort of world, which led us into a ditch in 1962. Finally, in regard to the United States in dealing with foreign policy, please look at the objectives of the U.S. in this region, its perception of current state of affairs, as I mentioned to you, of who they regard as central, and third its present compulsions. Then you would have a more realistic view. Sir, I come now to paragraph 12 which deals with defence. Sir, I have 4 points to make. First, it is not Antony's fault, it is not any particular person's fault, but it is a fact that both in the acquisitions and development of our weapon systems, we have not progressed as rapidly as our engineering, technical capacities entitled us to progress and as the situation demands. It is said that this is because allegations are made, inquiry starts. Therefore, the honest officers delay the decision. That is not the case. Sir, the point is, just now also you had to freeze acquisitions from 7 firms. The fact of the matter is that these decisions get delayed because the inquiries are made to drag on forever, and because the guilty are not punished. Therefore, my request to you is three-fold. First, act with lightening speed on those inquiries; second, punish; an exemplary punishment to whoever is guilty; third, demonstrate by your own actions that you will stand by the honest officers. This is required. There is nothing controversial. But I can give you an example. Just now, there are allegations

about some Air India fellow getting caught in some trap. Why don't you sequester. The telephone conversations of that ordinance chap were tapped for three months before his arrest. You get the seizure memo from this Air India fellow's house, what has been recovered. From what we know is that the management of that Ghosh's accounts were recovered from this Air India fellow's place, and there are all sorts of reports of where he had been visiting. Sequester. Get hold of all those visiting registers. Then you can make a demonstration that yes, we will conclude this trial, we will conclude this investigation in two weeks, in three weeks, and thereby either you blacklist some firms or you get rid of some firms. That is one point on acquisitions. Second point is, I have been on the Defence Committee, and we have all been very supportive. The country is proud of its scientists. But it is also a fact that many vital DRDO projects have got greatly stretched up. Arjun tank is just one example. I do not want to give many examples of this kind. But on the other side, India is one of the very few countries in which in the private sector, technical, engineering, scientific capacity has been built up in a very big way. So, this is an area in which we really should push ahead what everybody has talked. If I am not mistaken, even the Prime Minister has said about public-private partnership. But I remember the Defence Minister and others saying this that we should push it. Tap the energy and expertise which has developed in India so that we really become much more secure than we are at present. It always amazes me कि अरे, प्राइवेट सेक्टर आएगा, सिक्योरिटी आएगी। But we do not feel insecure when the entire weapon system is bought from a private firm abroad.

So, that is my first point, Sir, on acquisitions and development of weapons, and you will not find its mention, at all, in paragraph 12. The second point, Sir, is on civil-military relations. We have never had an occasion, never in 60 years, when the officers who were in senior most positions in the Indian Armed Forces had returned their medals when they came out on the streets, as happened just a few months ago. And it was not just because of 'one rank-one pension'; the point is mentioned in paragraph 12. It is because of the entire approach of the Pay Commission in regard to this. And they feel that yes, there is an extreme shortage of officers in the Armed Forces. In the Army alone, there is a shortage of more than 20,000 or 25,000 officers and that is the shortage which is hitting in the field-formations because everybody is packed up in the headquarters; that is why the officer and the

Jawan relationship is getting tenuous and, therefore, you have cases of suicides or assaults as Gill Sahib and others would note. In spite of that, the Pay Commission, Armed Forces feel, was so controlled by the civil servants and others that the Civil Services got much more and the Armed Forces did not get. That is a much wider issue than the just 'one rank-one pension' issue which deals with only retired officers. So, I would urge you to please look at that entire gamut; maybe, expand the terms of reference of the Committee which you have set up in this regard, beyond that single question of 'one rank one pension'. The second point, Sir, here, is that actually speaking, there is a deeper problem in civil-military relations, and that is a feeling which many people in the Armed Forces have because I happen to go to them, very often, for lectures and other things, that they do not have the voice in determining threat assessments and strategic responses in regard to that. This is not a partisan matter. It is not that the UPA did it or the NDA was doing something else. Over the years, they had not been involved as experts in this whole formulation--I do not want to go into this because it involves delicate matters. I will give you just one instance. Sir, in 2006, the Armed Forces, Mr. Antony will remember, were asked to draw up a national strategic paper, you know, on assessments and responses. Do you know--I am sure, you would know, Sir, --that since January 2007--we are now in the 2009 June-that draft prepared by the Armed Forces has been lying on or in the desk of a civilian officer and has not moved, so much so that the former Chief of Staff of the Army, Gen. Ved Malik, was constrained to go public on this अरे भाई क्या कर रहे हो। And it is this matter, the civil-military relations, Sir, that, I feel, should be attended to. They are not reflected in paragraph12.

Sir, the third situation I have is that by looking at the sequence of things that are happening, because each time whenever there is an assault on India, we turn out to be, actually speaking, a country without options, we go through many types of विनोबा भावे कहा करते थे कि हमारे यहां बात का काम ही काम है, काम की बात नहीं है। we go through the cargos, the motions of doing something, not doing something, because we have not built up the capacity which a pacifist country, a peaceful country must have, and that is to deal with the entire spectrum of violence; not just nuclear weapons, not just one terrorist, but the entire spectrum, because the enemy chooses what kind of violence that he will unleash. Now, Sir, in this regard, I will draw your attention to one small matter, and because my good friend Raja is here, I will take that up, Sir. Sir, you look

at the end of paragraph 9. Because Mr. Chidambara is in the Home Ministry, he is attending to systems; he is not just shuffling individuals; he is not just holding meetings.

He says--this is quite the kind of words that he had used--"Enhanced information and intelligence sharing on a real time basis, would be made possible by the creation of a net centric information command structure". I am sure that these words are not there because they are fashionable or current words, but because this is the capacity that we should acquire. But you know, as the economies get integrated, they become more vulnerable. An integrated power grid can be hit at a few points and the power supply to North India is finished. When you have net-centric command structures, as has been done in the Defence Forces and Mr. Chidambaram is going to do it with our police forces, you become capable but you also become more vulnerable. In 1989, the President of China at that time declared, "We will recruit an army of hackers", and they demonstrated this capacity again and again by targeting the Pentagon system. Every fortnight they have a report on this. They have a strategy of hitting at the acupuncture points of the society so as to disable it. Now, Mr. Raja is my very dear friend. But I have watched, Sir. I have never said this in public. I have watched with great dismay the initiatives which were taken with the Armed Forces and found the Ministry of Information Technology building fire-walls around our infrastructure, building fire-walls around our banking and financial transaction structures and building fire walls around our airport and railway traffic control systems. These are the acupuncture points, the integrated power grid. A lot of effort was started in this direction. I don't want to make any allegation. I watched with dismay and I would only plead with Mr. Raja, please do your best, as I am sure that you will, in regard to this because it is not just net centric warfare, a command structure. Behind that lies great vulnerability as well as great potential. The next point is this. I can give you an example. In the United Kingdom and in the United States, for this very reason--because they had seen that backdoors were put, because they had seen that things were built into chips, which can be triggered by magnetic pulses-all telecom infrastructure from China was banned. There was a note of the National Security Advisor, when I was there; to this effect and how suddenly that has been disregarded is a different thing. If we talk on these matters later, I would disclose to you the papers and the minutes of what transpired in the meetings. So, this net-centric type of

things is very necessary, but it also requires other work and, therefore, I would urge upon Mr. Antony, please pay great care that we associate with you to this question of meeting the entire spectrum of violence in this regard. The next point is the imminent threat. Mr. Satyavrat has mentioned this. He said, "China has encircled India", and he urged upon the Government to pay attention to this. But the fact of the matter is that on two counts, because of outsourcing or paralysis of our Government, this encirclement has got greater scope and has been speeded up and facilitated. One was the paralysis that occurred in regard to the developments in Nepal and the ultimate outsourcing of the foreign policy to my friend, Mr. Sitaram Yechury. That had consequences. It gave China a great opportunity in Nepal.

सारांश

मैं सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैराग्राफ 41 से 44 पर कहूँगा, जो विदेशी नीति से संबंधित हैं और तत्पश्चात् पैराग्राफ 12 पर कहूंगा जोकि रक्षा से संबंधित है। यद्यपि चीन, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सु.वम संबंध बनाने के संबंध में लोकप्रिय अभिव्यम्तियों का प्रयोग किया गया है। परंतु स्थिति अत्यधिक विकट है। मुम्बई हमले के बाद मैंने अनेक बातों का अनुरोध किया था परंतु मुझे केवल दो बातें याद हैं। मेरी पहली बात यह थी कि पाकिस्तान को कोई साक्ष्य मत भेजिए, क्योंकि इससे आप पाकिस्तान को जज की स्थिति में रखेंगे और पाकिस्तान आपके तर्क को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक वही बात हुई। हम वही हैं, जहां मुम्बई हमलें के बाद थे।

दूसरी चीज हम पाकिस्तान और चीन के खतरे से निपटने के लिए बुरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर हो गए हैं जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका स्वयं पाकिस्तान और चीन पर विभिन्न कारणों से निर्भर है। वे पाकिस्तान पर इसलिए निर्भर है कि वे उस क्षेत्र में तब तक लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं जब तक वे सम्मानजनक रूप से वहां से निकलने में सक्षम न हों। वे चीन पर आज इसलिए निर्भर है कि चीन अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रहा है। चीन पहले ही सबसे बड़ा बॉन्ड धारक है।

तीन ऐसी घटनायें हैं जो बहुत बड़ी समस्यायें पैदा कर रही हैं। इनमें से पहली है, परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा जोकि 2010 में होनी है और भारत पर इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अत्यधिक दबाव डाला जायेगा और वह भी परमाणु शस्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए बिना।

दूसरी बात, भारत पर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जायेगा ताकि यह प्रभावी हो सके। यद्यपि अमेरिकी सीनेट ने सीटीबीटी को अस्वीकार कर दिया है। तीसरी बात, भारत पर फिसाइल मैटीरियल नियन्त्रण संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जायेगा जोकि पहले ही उनके वक्तव्यों में दिखाई देने लगा है। चौथी बात, हमें पीएसआई पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जायेगा जिसके के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह वर्तमान रूप

में भेदभावपूर्ण है और हमें इस पर आपत्तियां हैं। अंत में 'आईएईए' में अधिक कठोर अतिरिक्त प्रोटोकॉल जोड़ने का प्रस्ताव है जोकि गत वर्ष से भी कठोर होगा।

दूसरी बात, जो मैं दबाव के बारे में कहना चाहूँगा, वह पाकिस्तान के साथ तथाकथित शांति प्रक्रिया बहाल करने के संबंध में होगी जोकि पाकिस्तान को रियायतें देने के लिए होंगी। वे उत्तरी–पश्चिमी सीमांत क्षेत्र स्वात में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। परंतु वे पंजाब तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी वमांचों के संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका से आग्रह करने से कुछ नहीं होगा। वे हमारा काम नहीं करेंगे और इस संबंध में हमारे हितों को ध्यान नहीं रखेंगे।

तीसरी बात, जिसका विदेशी नीति और रक्षा से अधिक संबंध है वह है हमारी अपनी सुरक्षा के प्रबंधन के संबंध में दबाव। प्रत्येक देश अपने हितों को देखेगा। एक समय था जब सद्दाम हुसैन ईरान का सामना करने के लिए बहुत अच्छा था, उसे वित्तीय सहायता दी गई, संरक्षण दिया गया और प्रोत्साहित किया गया। लेकिन दूसरे ही दिन वह राक्षस बन गया। आज तालिबान बहुत अच्छा है, उन्हें सृजित किया जाना चाहिए, उन्हें संगठित किया जाना चाहिए, उन्हें सोवियत सैनिकों को निकालने के लिए हथियार दिए जाने चाहिये। कल वे राक्षस बन जाते हैं। इसलिए अपने हितों की रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए।

अब मैं पैराग्राफ 12 पर आउंगा जोकि रक्षा से संबंधित है। इस संबंध में मुझे चार बातें कहनी है। पहली बात, हमारी शस्त्र प्रणाली के अर्जन और विकास में दोषपूर्ण व्यवस्था का विद्यमान होना है। हमने अपनी इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षमताओं का उतनी तेजी से विकास नहीं किया है जितना हमें करना चाहिए था और जैसेकि स्थिति की मांग थी। हथियारों के अर्जन के संबंध में देरी का कारण रक्षा सौदों में जांच किया जाना है। इस संबंध में मैं तीन सुझाव देता हूँ। पहला, उन जांचों को पारदर्शिता से निपटाया जाए। दूसरी बात, दोषी को दण्डित किया जाए और तीसरी बात, ईमानदार अधिकारियों का बचाव करते हुए अपने कार्यों को प्रदर्शित कीजिए।

अनेक डीआरडीओ की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बहुत विलम्ब हुआ है। अर्जुन टैंक इसका एक उदाहरण है। भारत उन बहुत कम देशों में से है जहां निजी क्षेत्र, तकनीकी, इंजीनियरी, वैज्ञानिक क्षमता काफी विकसित हुई है। यह आश्चर्यजनक है जब हम विदेशी निजी कंपनियों से शस्त्र खरीद सकते है तो भारत में शस्त्र विकास के लिए निजी भागीदारी क्यों नहीं कर सकते।

सेना में ही बीस या पच्चीस हजार से अधिक अधिकारियों की कमी है और यह कमी फील्ड कंपनियों पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं क्योंकि प्रत्येक व्यम्ति मुख्यालय में भेजा जाता है। इसलिए अधिकारी और जवानों के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं और आत्महत्यायें और हमलों के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, सिविल सेना संबंधों की अधिक गम्भीर समस्या के संबंध में है। 2006 में सेनाओं को मूल्यांकन और प्रतिक्रियाओं पर एक राष्ट्रीय रणनीति पत्र तैयार करने के लिए कहा गया था।

सशस्त्र सेनाओं द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया जोकि आज भी असैनिक अधिकारी की मेज पर लंबित पड़ा हुआ है और उस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। इसको देखते हुए सेना प्रमुख जनरल वेद मलिक को सार्वजनिक रूप से इस संबंध में कहना पड़ा। परंतु, सेना सिविल संबंधों का उल्लेख पैराग्राफ 12 में नहीं

किया गया है। तीसरी स्थिति, जो मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि हरेक समय जब भी भारत पर हमला होता है तो हम बिना विकल्पों वाला देश बन जाते हैं।

यह उल्लेख किया गया है कि 'समय पर सूचना और खुफिया जानकारी आदान–प्रदान किया जाना इस संपूर्ण केन्द्रीय.त सूचना कमांड संरचना से संभव हो सकेगा। यह क्षमता प्राप्त की जानी चाहिए। लेकिन जब हम संपूर्ण केन्द्रीय. त सूचना कमांड संरचना तैयार कर लेते हैं जैसा कि रक्षा सेनाओं के मामले में किया जा चुका है, हम सक्षम तो हो जाते हैं लेकिन साथ ही हमारी स्थिति और अधिक सुभेद्य हो जाती है।

अतः इस प्रकार की संपूर्ण केन्द्रीयकृत संरचना अतिआवश्यक है लेकिन इसके साथ ही अन्य कार्य करने की जरूरत पड़ती है और मैं इसलिए माननीय रक्षा मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में हिंसा से पूरी तरह से निपटने हेतु और अधिक सतर्कता बरती जाए।

श्री सत्यव्रत ने कहा है कि चीन ने घेराबंदी कर दी है और उन्होंने सरकार से इस बारे में ध्यान देने का अनुरोध किया है। हमारी सरकार के पंगु हो जाने अथवा इसके द्वारा आउटसोर्स कर देने के कारण इस घेरेबंदी की और अधिक संभावना बन गई है। नेपाल में हुई घटनाओं के संदर्भ में जो हमारे द्वारा निष्क्रियता बरती गई, उसके कारण चीन को नेपाल में अपना प्रभाव जमाने का बड़ा अवसर मिल गया।

श्रीलंका के मामले में हम पंगु बने रहे हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित किया गया। चीन ने तमिल आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई। इस प्रकार से उन लोगों दक्षिण में भी हमारी तुलना में अधिक प्रभाव हासिल कर लिया। दूसरे, हर दूसरे–तीसरे महीने चीन अरूणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है। सुरक्षा परिषद में सुधार, आसियान देशों के साथ संबंध, या किसी भी अन्य मामले में भारत ने जब भी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की, चीन ने बाधा खड़ी कर दी है।

वह भारतीय सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण जारी रखे हुए है। आईटीबीपी के महानिदेशक ने बताया है कि वर्ष 2007 में 170 से अधिक बार अतिक्रमण किया गया। वर्ष 2008 में और अधिक बार अतिक्रमण किया गया है। आईटीबीपी के कर्मियों का कहना है कि इन घटनाओं पर कार्रवाई करने का अनुदेश नहीं मिला है। रक्षा सेना के मामले में स्थिति बहुत अधिक जटिल है।

मैं सरकार से इन मामलों में देश को विश्वास में लेने का अनुरोध करता हूं। जबतक वास्तविक घटनाओं के बारे में लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तो फिर यदि 1962 जैसी घटना फिर से हो जाए तो लोग एक बार फिर से भौचंके रह जाएंगे।

पिछले 5 वर्षों, विशेषकर वमाई वर्षों के दौरान, वित्तीय फिजूलखर्ची के कारण, हमारा घाटा ऐसे स्तर पर पहुंच गया है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कह दिया है कि आगे और किसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के लिए बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं बची है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि .पया समय पर कार्रवाई की जाए; इसे साधन के रूप में प्रयोग नहीं करके स्थिति पर नियंत्रण कायम किया जाए। आज आप मुख्य प्रोत्साहन यही दे सकते हैं कि परियोजनाओं को और अधिक तेजी से पूरी करवाएं। प्रधानमंत्री ने कार्यान्वयन के

गुणवत्ता में सुधार लाने तथा वितरण तंत्र की कार्यकुशलता और जबाबदेही बवमाए जाने पर बार–बार जोर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अब यह कहा गया है, 'एक वर्ष के अवधि के दौरान योजना आयोग के साथ मिलकर हम सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकासात्मक परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु एक तंत्र का निर्माण करेंगे'। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले का तंत्र कार्य नहीं कर रहा है। व्या अभी तैयार किया जाने वाला तंत्र पहले के तंत्र से कुछ अलग होगा? यह कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की समस्या मात्र है।

मैं एक सुळााव देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। आपने जिस प्रकार से त्वरित सिंचाई का कार्यक्रम, त्वरित विद्युत परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए थे जिसके अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर यथा निर्धारित लागत में कार्यान्वित करने वाले राज्यों, फर्मों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को पुरस्.त किया जाता था। अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रोत्साहन उसी से आएगा।

जब डा. मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, श्री चिदंबरम वित्त मंत्री बनाए गए थे और श्री मोंटेक सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा था कि यह एक स्वप्निल टीम है। तथ्य यह है कि उस गति से और उतना अधिक सुधार नहीं देखने को मिला जितनी कि उस टीम से उम्मीद की गई थी। ऐसा न कर पाने की सारी जिम्मेदारी वामपंथियों पर डाल दिया गया था। अब वह बाधा या बहाना नहीं है।

इस समय .पया इस कार्य में तेजी लाई जाए। पैरा 34 विनिवेश के बारे में है। वर्ष 1991–98 के दौरान किया गया विनिवेश काफी खराब सिद्ध हुआ। शेयर बेचे गए; यूटीआई और अन्य संस्थाओं के हवाले शेयर कर दिए गए लेकिन उस विनिवेश के कारण प्रतिष्ठानों के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। जो भी धनराशि प्राप्त हुई वह वित्तीय घाटे के गर्त में समा गई जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। और वस्तुतः इस प्रकार के विनिवेश से वित्तीय अनियमितता को बवमावा मिलता है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित पैरा के बारे में, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करें। इस देश में जो कोई भी वंचित हो, उसकी सहायता किए जाने के सवाल पर मैं आपके साथ तथा इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा हूं लेकिन हमें यह कार्य पंथनिरपेक्ष आधार पर किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति का चयन किए जाने के मामाले में पंथनिरपेक्ष मानदंडों का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसा कि हम उदाहरण के लिए एपील और बीपीएल परिवारों के मामले में आय और परिसम्पत्तियों का निर्धारण करने में किया जाता है।

एक प्रकार के व्यक्तियों के समूह को दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के समूह से विभाजित रखना अंग्रेजी शासन की नीतियों का अनिवार्य अंग हुआ करता था जिसके कारण हमारा देश बर्बाद हो गया और उस व्यक्ति को वह लाभ इसी आधार पर दिया जाता था कि वह समाज के शेष भागों से अलग–थलग बना रहेगा, पृथक निर्वाचन आदि इसके उदाहरण हैं। आन्ध्र में जो कुछ हो रहा है और सच्चर समिति के अधीन सरकार द्वारा जो कुछ भी किया जाना प्रस्तावित है, वह देश के हित में नहीं है।

हम एक बार फिर यह अनुरोध करते हैं कि सब्सिडी वास्तविक जरूरतमंद

और गरीब तक पहुंचनी चाहिए।

जहां तक प्रशासनिक सुधार का संबंध है, इसके बारे में 73 समितियां, कार्यशालाएं, आयोग गठित किए जा चुके हैं। हम सभी के मन में डा. मनमोहन सिंह के प्रति काफी आदर का भाव रहा है। हम लोग उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण आदर करते रहे हैं लेकिन तथ्य यह है कि गत 5 वर्षों के दौरान हो सकता है कि ऐसा मजबूरीबश किया गया हो। मानदंडों की अनदेखी की गई और संस्थाओं का साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। सीबीआई तो महज एक उदाहरण है।

मुलायम सिंह, मायावती या लालू के विरुद्ध मुकद्दमे में सरकार ने उनके द्वारा दिए गए समर्थन के आधार पर कार्यवाई की। अतः मानदंड बदले गए और संस्थाओं का साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्रमुख तौर पर इस स्थिति में सुधार किए जाने की जरूरत है। अतः अनुरोध है कि संस्थाओं की पवित्रता बहाल की जानी चाहिए।■

वास्तविकता से परे है अभिभाषण के तथ्य

& dyjkt feJ

आदरणीय उपसभापति जी, 15वीं लोक सभा के गठित होने के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो संयुक्त अधिवेशन को उद्‌बोधित किया है, उसमें एक तरह से पांच वर्ष के लिए इस सरकार के एजेंडा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। सामान्य तौर पर हर वर्ष बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है और वर्ष के अंदर क्या–क्या एजेंडा सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा, इस बात को इंगित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन 15वीं लोक सभा के गठित हो जाने के पश्चात पांच वर्ष का एजेंडा यहां प्रस्तुत किया गया है और उसमें दस बिंदु प्रमुख रूप से रखे गए हैं, जिनमें कहा गया है कि इनके आधार पर हम देश के अंदर विकास की प्रक्रिया को तेज़ करेंगे। उन दस बिंदुओं में जो पहला ही बिंदु इन्होंने भाषण के दौरान सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया है, वह है – आंतरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्‌भाव बनाए रखना। यह स्वाभाविक रूप से यह लगा कि पांच वर्ष का जो काल था, उस काल में सरकार ने जो कार्य किया, उसका लेखा–जोखा क्या है, जो इस प्रकार की घोषणा की गई है, उस घोषणा के अनुरूप काम हुआ है या नहीं हुआ और जब यह पहला ही बिंदु देखा गया कि आंतरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव पर ज्यादा ज़ोर दिया जाएगा, इसको बनाए रखा जाएगा, तो इसको पक्ते ही लगा कि आंतरिक सुरक्षा तो गत पांच वर्षों के अंदर सर्वाधिक बाधित रही है।

बाधित इसलिए रही कि जहां देश के अंदर नक्सलवाद, माओवाद, आईएसआई, सिमी – इस प्रकार के तत्व उपद्रव करने में शामिल थे, वहीं आतंकवाद का प्रकोप भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा था। उसके अंदर पोटा समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण आतंकवादियों के मन में जो भय बना हुआ था, उस पोटा कानून के समाप्त होने के कारण उनके मन के अंदर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और उन्हें लगा कि अब तो ऐसी सरकार आ गयी है मानो वह किसी न किसी रूप में हमारे प्रति मुलायमियत बरत रही है। उसी का परिणाम हुआ – 26 नक्बर को मुम्बई की घटना। मुम्बई में सीधा–सीधा हमला था। उसका कई तरीके से लोगों ने वर्णन किया है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर रहा है कि केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी लगा कि भारत सरकार की इस संबध में जो नीतियां रही हैं, वे नाकाबिल साबित हुई हैं, अक्षम साबित हुई हैं क्योंकि सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी गुप्तचरीय व्यवस्था, सारी पुलिस से संबंधित व्यवस्था, सबको धत्ता बताकर आतंकवादी मुम्बई में सशरीर घुसकर खुले आम हथियार चलाते हुए सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर गए। पूरे देश को उन्होंने स्तब्ध कर दिया था

और सचमुच इसने हमारी आंतरिक सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की अक्षमता को साबित किया है। इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर यह मांग की जाती है, यह कहा जाता है कि मुम्बई में जो घटना घटित हुई, इस घटना पर सम्पूर्णता से विचार करना चाहिए कि कहां खामी रही – केन्द्र सरकार की खामी रही, प्रदेश सरकार की खामी रही या और किसी प्रकार की कमी रही। इस पर सम्पूर्णता से विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में सम्पूर्णता से विचार करने के लिए अगर एक जांच आयोग गठित किया जाए और उसके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाए तो मैं समळाता हूं कि काफी चीज़ें सामने उभरकर आ जाएंगी। उस हिसाब से सही मायने में हम कुछ व्यवस्था कर सकेंगे। अन्य बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, उनके संबंध में हम नहीं बोलना चाहते३ दूसरा, साम्प्रदायिक सद्भाव की बात कही गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य यह रहा है कि जब यह कहा गया कि योजना के विकास के संसाधनों पर प्राथमिकता, तो एक सम्प्रदाय विशेष का नाम लेकर कहा गया है, बाकायदा 'मुसलमान' शब्द का नाम लेकर कहा गया है। मैं समझता हूं कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी के साथ मजहब को नहीं जोड़ना चाहिए। जब गरीबी के साथ मजहब जोड़ दिया जाएगा तो किस मजहब का आदमी गरीब होगा और किस मजहब का आदमी अमीर होगा, क्या इस तरीके से हम गरीबी और अमीरी को परिभाषित करेंगे? इस तरीके से गरीबी और अमीरी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के प्रधान मंत्री ने इस शब्द का प्रयोग करके साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं बनाया, बल्कि साम्प्रदायिक सद्भाव के अंदर आक्रोश पैदा करने की कोशिश की है।

इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें सीधे–सीधे वोट बैंक की राजनीति की गयी है क्योंकि जब मैंने देखा कि इसके लिए कितने जिलों को प्राथमिकता के आधार पर रखा गया तो पाया कि 121 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर रखते हुए उन जिलों में संसाधनों को, जो प्राथमिकता देने की बात कही गयी है, वहां प्रस्तुत किया जाएगा – उनमें से 42 सांसद कांग्रेस के जीत कर आए हैं। मेरा कहना है कि वोट बैंक की राजनीति करने की साजिश की गयी थी।

साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के नाम पर एक सम्प्रदाय विशेष का उल्लेख करते हुए देश के अंदर साम्प्रदायिक आक्रोश पैदा करने का और एक सम्प्रदाय विशेष को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है। इससे साम्प्रदायिक सद्भाव का निर्माण नहीं हो सकता है। मान्यवर, गरीबी इस देश के लिए एक अभिशाप है और यह एक ऐसा अभिशाप है कि अगर इससे प्रभावी तौर पर निपटने की कोशिश नहीं की गयी और केवल भाषण मात्र दिए जाते रहे तो गरीबी नहीं मिट सकती। अभी विश्व बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आयी है, Global Economic Prospects for 2009 . उसमें यह चेतावनी दी गयी है कि 2015 तक भारत की एक चौथायी आबादी चरम निर्धनता का शिकार हो जाएगी।

और इसमें यह भी कहा गया है कि 2007 तक दो करोड़ से ज्यादा गरीबों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। फूड सिक्योरिटी के नाम पर यह घोषणा जरूर की जा रही है कि हम तीन रुपये किलो खाद्यान्न देंगे। लेकिन तीन रुपये किलो खाद्यान्न देने से यह गरीबी समाप्त नहीं होने वाली है। गरीबी तो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है, इस रिपोर्ट को देखकर, कि आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि अमीरी और गरीबी के बीच में हिन्दुस्तान

के अंदर संघर्ष चलेगा और इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा जिसको जल्दी बचाया नहीं जा सकेगा। इस प्रकार इतनी भयंकर स्थिति निर्माण हो गई है। गरीबों को केन्द्र में रखते हुए जिस तरीके से उनके अनुरूप योजना बनानी चाहिए, उस योजना का जबर्दस्त अभाव है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि योजनाएं तो बहुत बनी हैं, योजनाएं तो इतनी अधिक बनी हैं कि अगर योजनाओं का उल्लेख किया जाए तो लगेगा कि इतनी योजनाएं बनीं और उनके बावजूद भी गरीबी खत्म नहीं हो रही है, आखिर उसका कारण क्या है? मान्यवर, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी हम गरीबी को दूर नहीं कर पा रहे हैं और गरीबों वाली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देश हैं, उसमें हिन्दुस्तान का 93वां नम्बर है। इस गरीबी को दूर करने में हम पूर्णतया अक्षम हुए हैं। योजनाएं भले ही हमने बनाई होंगी लेकिन उन योजनाओं को हमने कार्यान्वित नहीं किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न सुरक्षा योजनाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं और जनसामान्य के लिए जो योजनाएं हैं वह मैं बतलाना चाहूंगा। जनसामान्य को खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, महिला कल्याण विभाग है, ग्रामीण विकास है, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, काम के बदले अनाज आपूर्ति योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक हित योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना, इतनी सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इन योजनाओं के संचालन में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन योजनाओं के संचालन में अलग–अलग पैसे खर्च हो रहे हैं, अलग–अलग तरीके से जा रहे हैं, लेकिन उनका समन्वय नहीं है। अगर उनका समन्वय होता तो समन्वित क्रंग से इन संसाधनों पर सुनिश्चित एजेंसी काम करती तो शायद पर्याप्त मात्रा में हम गरीबी का उन्मूलन कर सकने में सक्षम होते। लेकिन यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। UNDP में श्रीमती अरुणा शर्मा ने प्रशासनिक सुधार के संबंध में एक रिसर्च की है। उनका यह कहना है बावन हजार करोड़ की अगर कोई विकास योजना है और समन्वित क्रंग से संसाधनों का सुनिश्चित एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन किया गया तो निश्चित रूप से बारह सौ करोड़ रुपया प्रत्येक गांव को प्राप्त हो सकता है, जहां पर योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है और गांव विकास के क्रम में आगे बक सकता है। लेकिन इस दिशा में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण गरीबी का नाम तो जरूर लिया जा रहा है, लेकिन गरीबी का उन्मूलन नही हो पा रहा है, गरीबों की संख्या बक्ती जा रही है और जब गरीबों की संख्या बक्ती जा रही है तो वे भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं, उनके घरों में बच्चों की पक्राई नहीं हो पा रही है, वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकने के कारण जिस तरीके से आत्म–निर्भर होकर लोगों के बीच में स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर चलने की मानसिकता बननी चाहिए, आज हिन्दुस्तान के अंदर 35 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो इस हालत में नहीं हैं। कहा जाता है कि साक्षरता अभियान चलाया गया और अभी जो यह चुनाव हुआ है उसमें कहीं–कहीं 85 फीसदी वोट पड़े हैं। लेकिन मान्यवर, शिक्षा की दृष्टि से हालत यह है कि अंगूठे छाप ज्यादा हैं। आंकड़ों में तो कहा जा रहा है 75 फीसदी से ज्यादा साक्षर हो गए हैं।

लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं। हमने 35

करोड़ की बात बताई, इतने लोग हैं, जो अंगूठा छाप के आधार पर ही सारा काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर वोट देकर शासन तो उन्होंने स्थापित किया, गद्दी पर तो उन्होंने लोगों को बैठा दिया, लेकिन लोकतंत्र का आर्थिक दृष्टि से, उनके जीवन के अंदर जो सदुपयोग होना चाहिए, उस प्रकार की योजना के अभाव के कारण वे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए गरीबों की विकराल संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। यह सरकार कह रही है कि हम करेंगे। कैसे करेगी यह सरकार? सरकार ने जो आर्थिक व्यवस्था का चित्रण किया है, हमारे कई सत्तारूढ़ दल के मित्रों ने उसके संबंध में बताया है।मैं बताना चाहूंगा कि 4 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। 34 लाख करोड़ डोमेस्टिक कर्जा है और 221 करोड़ डालर विदेशी कर्जा है। इतने कर्जे हैं और सात फीसदी का ग्रोथ रेट है। यह हालत, यह आर्थिक स्थिति हमारे सामने उपस्थित है। केवल इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए हैं, पिछले तीन महीने के अंदर औद्योगिक उत्पादन ही नहीं घटा है, बल्कि निर्यात में भी 30 से 35 फीसदी की कमी आई है। अर्थ–व्यवस्था में मजबूती का मुख्य आधार बिजली का उत्पादन है। यह गत वर्ष 6.4 प्रतिशत था, उसकी तुलना में अब यह 2.3 प्रतिशत रह गया है। बिजली का उत्पादन कहां से होगा ? यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। इतना ही नहीं, सरकार जो प्रोत्साहन पैकेज दे रही है, वह अपर्याप्त है। इसमें कुछ नहीं चल सकता है। 65 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करना, विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण को आसान बनाना, शुल्कों में कमी करना और कुछ क्षेत्रों में स्वयं खरीददारी करके, अनेक कदम उठाकर उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है, लेकिन अर्थ–व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है ? पिछली बार अंतरिम बजट पास किया । उस अंतरिम बजट के अंदर 5.6 प्रतिशत घाटा आंका गया था, लेकिन इस बार जो बजट पास होने वाला है, जो आकलन आया है, उस आकलन के आधार पर 13 फीसदी से ज्यादा घाटा बक जाएगा। आप आर्थिक स्थिति कैसे सुव्यवस्थित करेंगे ? इससे भयंकर स्थिति तो आम आदमी पर कर्जा है। यह कर्जा आम आदमी पर, जो गरीब आदमी है, उसका जो दस माह का खर्चा है, उस गरीब आदमी पर उसकी दस माह की आय के बराबर कर्जभार है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के ताजा सर्वेक्षण के आधार पर 115 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रति व्यक्ति आय 38 हजार रुपये प्रति व्यक्ति बताई है। अर्थ व्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए सरकार जिस तरीके से बाजार से उधार लेकर सार्वजनिक निवेश बक्ने में लगी है, उससे अनुमान है कि मार्च, 2010 तक प्रति व्यक्ति सार्वजनिक ऋण का भार 30 हजार रुपये तक हो जाएगा। सरकार पिछले कुछ वर्षों से हर साल करीब 3 लाख करोड़ का उधार ले रही है। अगले साल मार्च तक यह कर्ज 34 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। कर्जों का ब्याज भार वर्ष 2008–09 में 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये से बक्कर 2009–10 में सवा दो लाख करोड़ हो जाएगा। यह हमारे देश की आर्थिक स्थिति है। ऐसी आर्थिक स्थिति में आप क्या करेंगे ? किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, उसने बताया है कि 2007 में एक लाख 22 हजार से अधिक आत्म–हत्याएं हुई हैं और जिसमें 14.7 फीसदी किसानों ने आत्म–हत्याएं की हैं । किसान के कर्ज माफी की बात तो कही जाती है, लेकिन किसान की जो आम सुविधाएं हैं, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है, जैसे

छोटी जोत है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 11 करोड़ 50 लाख परिवार ऐसे हैं, जो किसान परिवार हैं, जो कृषि पर निर्भर हैं और एक करोड़ 70 लाख ऐसे परिवार हैं, जो भूमिहीन परिवार हैं।

इनकी ऐसी हालत है कि जो भी योजना सुनिश्चित की जाती है, उससे लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चाहे किसान कर्ज़ा लेकर आत्महत्या करने के लिए मज़बूर होता है, चाहे उसका समुचित उत्पादन न होने के कारण तथा पेट भरने के लिए अन्न न मिलने के कारण, वह आत्महत्या करने के लिए मज़बूर होता है, चाहे जो महंगाई आसमान छू रही है, उसके कारण आत्महत्या करने के लिए मज़बूर होता है। कहा गया है कि महंगाई घट गई है, मुद्रास्फीति .48 परसेंट हो गई है। यदि मुद्रास्फीति .48 परसेंट हो गई है, तो फिर महंगाई आसमान क्यों छू रही है? दाल 60 रुपए किलो बिक रही है और नमक का दाम 10 रुपए किलो हो गया है। सरसों के तेल का दाम 90 रुपए किलो गया है। जो लोग ये चीजें खरीदते हैं, वे बताते हैं। अभी उस दिन जनेश्वर मिश्र जी सब्जी के दामों के बारे में बता रहे थे कि आलू का दाम 14 रुपए किलो हो गया है। आम आदमी भोजन करने को मोहताज हो गया है। मान्यवर, हमारे यहां कहा जाता था कि 'भूल गया राग–रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी' । आज लोगों के सामने नून, तेल, लकड़ी की समस्या खड़ी हो गई है। इसके साथ ही ईंधन और बाकी के सभी सामानों की समस्या भी खड़ी हो गई है।

इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि राष्ट्रपति अभिभषण के ये बड़े–बड़े पन्ने पक्ने के बाद तो यह लगा कि शानदार चित्र दिखाया गया है और बताया गया है कि हमें जनादेश प्राप्त हो गया है, लेकिन यह तो Fractured Mandate है, विखंडित जनादेश है। मैं इसको विखंडित जनादेश इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस 206 सीटों पर जीती है और यूपीए 261 सीटों पर जीती है। यह कोई सिम्पल मैजोरिटी नहीं है, ये जो इतने इतरा रहे हैं, गर्वोक्ति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने पाप किया है और उन्होंने बडा पुण्य कर लिया है। जिस तरह से प्रस्ताव कर्त्ता ने भाषण दिया था, उससे लगता था कि क्या कर रहे हैं! आप तो दो बार बहुमत में थे, लेकिन हम तो एक बार ही सरकार में थे। आप थ्तंबजनतमक डंदकंजम प्राप्त करने के बाद भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन आपके हालात तो ऐसे हैं, फिर इन हालातों को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए। आपने सौ दिन का कार्यक्रम बनाया है। इस सौ दिन के कार्यक्रम में कहीं पर भी गरीबों के बारे में कहीं कुछ नहीं है, किसानों के संबंध में कहीं कुछ नहीं है, राजकोषी घाटे का प्रबंधन कैसे होगा, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं है। आप इस सौ दिन के कार्यक्रम में कुछ ऐसा करके दिखाते, ताकि गरीब को भी लगता, किसान को भी लगता और आम आदमी को भी लगता कि हमारे जीवन में उन्नयन लाने के लिए सरकार कुछ कर रही है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए खड़े हुए हैं। हम आपके सामने जो चीजें रखेंगे, तथ्यों के आधार पर रखेंगे। जो कार्यवाही की गई है, उसकी समीक्षा करने के बाद रखेंगे और अपेक्षा करेंगे, उसको सकारात्मक दिशा में लेकर, उसके लिए कैसा कदम उठाया जाए, ताकि आम आदमी लाभांवित हो सके, यह प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इतनी ही बात कहकर माननीय उपसभापति महोदय की आज्ञा से अपनी बात समाप्त करता हूं।

Synopsis

In the President's Address, an attempt has been made to present agenda for five years of this government. This agenda presents ten main points. Firstly, it has been spelt that the government is committed to maintain internal security and communal harmony. It appears that during the last five years, internal security remained largely disturbed. The reason was that the elements like naxalites, Maoists,

ISI, SIMI were involved in creating disturbances and terrorism also increased very rapidly. Meanwhile, POTA was scrapped and as a result of this, fear got dispelled from the mind of the terrorists and they felt that the new regime was softening its stand towards them. The incident of 26th November at Mumbai was outocme of that feeling. This incident requires consideration of the matter in its entirety as to where shortcoming occurred at the level of Central Government or State Government or at some other level. Constitution of an inquiry commission on this issue will reveal so many things.

Second point has been mentioned with regard to communal harmony. Unfortunately it was stated that priority should be given to a specific community in regard to resources of development. I feel that issue of poverty should not be associated with any particular religion. Poverty and prosperity cann't be defined on the basis of religion. But the Prime Minister of India by giving such statement tried to destabilize communal harmony instead of creating communal harmony. A conspiracy to play vote bank politics. Effort has been made to attract a particular community towards itself. Communal harmony cannot be created with such things. Poverty is a curse for this country. If it is not dealt with effectively and mere speeches are delivered, it will never come to an end. A declaration has been made in the name of food security that they will provide food grains at the rate of Rs. 3/- per KG. But providing food grains at the rate of Rs. 3/- will not eradicate the poverty. We are not able to eradicate poverty in spite of being self reliant in the field of food grains and India is on 93rd position among 119 countries in Global Hunger Index. The schemes which have been framed for the poor, have not been implemented properly. Public Distribution system and Food Security Schemes are not functioning properly. So many schemes are being pursued but there is no coordination in their implementation. Had there been proper coordination in implementation, we would have been able to eradicate the poverty. The poor people are not getting the benefit due to the

lack of plan. So, their population is growing rapidly. Our domestic loan is Rs.34 lakh crore and foreign loan is 221 crore dollars. The growth rate is seven per cent. The power generation is the base to strengthen the economy. There was a fiscal deficit of about 5.6 per cent has been evaluated in interim budget. For the last some years the Government is taking the loan of 3 lakh crores every year. This loan will be Rs.34 lakh crores till March, next year. The farmers are living in hardships. About 14.7 per cent farmers have committed suicides. They are committing suicides due to the rising prices. The prices of everything is rising. Common man is helpless for getting the food. You have prepared the 100 days plan. There is no mention about farmers, poor people and fiscal deficit in the President's Address. ■